twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

# DD दिव्य दिल्ली

RNI No. DELHI/2013/54397

divyadelhi.com | रविवार, 03 अगस्त, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 258, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

## प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्र कैद

**बंगलूरू**

कर्नाटक की विशेष अदालत की तरफ से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिए गए जनता दल सेक्युलर (जदएस) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट्ट ने सजा का एलान किया। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म के चार मामले दर्ज हैं। मामला 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले में रेवन्ना के परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी।

**प्रज्वल रेवन्ना पर क्या हैं आरोप**

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पौत्र रेवन्ना 2021 में हासन के फार्महाउस और बंगलूरू में अपने घर में महिला के साथ दो बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। उसने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था। साथ ही धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो लीक कर देगा।

**पीड़िता की गवाही रही अहम**

विशेष सरकारी वकील अशोक नायक ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से बयान लिए और 180 दस्तावेज जमा किए। मुख्य साक्ष्य पीड़िता का था, जो बहुत ही विश्वसनीय था। मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने सितंबर 2024 में 1,632 पेज का आरोपपत्र दायर किया था। इसमें 113 गवाहों के बयान शामिल थे।

## जल विद्युत परियोजना स्थल पर भूस्खलन, आठ मजदूर घायल

**ज्योतिर्मठ**

चमोली जिले के ज्योतिर्मठ के हेलंग में टीएचडीसी की ओर से निमार्णाधीन विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के डेम साइट पर शनिवार को भूस्खलन हो गया है। जिससे परियोजना निर्माण कार्य कर रहे आठ लोग घायल हो गए थे। घटना की सूचना मिलने पर तहसील प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जहां रेस्क्यू कर सभी घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि हेलंग में हुई घटना के दौरान किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना में आठ लोगों के घायल हुए हैं।

# काशी: सिंदूर के बदले का वचन पूरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

## देशभर के किसानों को 20,500 करोड़ की सम्मान निधि की जारी

### प्रधानमंत्री ने काशी को दी 2200 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं की सौगात

**वाराणसी**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी के सेवापुरी स्थित बनौली गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने करीब 2200 करोड़ रुपये की 52 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तहत 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए। कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित एक लघु चलचित्र का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें योजना की सफलता और किसानों पर उसके प्रभाव को दर्शार्या गया। इस दौरान उन्होंने देशभर के व्यापारियों और नागरिकों से आह्वान किया कि अगर हमें देश को दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनाना है तो इसके लिए हमें स्वदेशी को अपनाना ही होगा।

**भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना होगा**

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वैश्विक चुनौतियों, स्वदेशी

अपनाने की आवश्यकता और किसानों की खुशहाली पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर ले जाना चाहता हूं। दुनिया में अस्थिरता का माहौल है। दुनिया के देश अपने-अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे किसान, लघु उद्योग और नवजवानों के रोजगार का हित सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिकों के रूप में हमें भी कुछ दायित्व निभाने होंगे। प्रधानमंत्री ने जनता से स्वदेशी का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था

### हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री ने सरकार की किसान-केंद्रित नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर की गई घोषणाएं पूरी होना मुश्किल था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है, वो करके दिखाती है। पीएम किसान सम्मान निधि को सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बताते हुए उन्होंने 2019 में योजना शुरू होने के समय विपक्षी पार्टियों (जैसे सपा और कांग्रेस) द्वारा फैलाई गई अफवाहों का जिक्र किया। विरोधी कहते थे कि चुनाव के बाद योजना बंद हो जाएगी या पैसा वापस ले लिया जाएगा, लेकिन "क्या इतने साल में एक भी किस्त बंद हुई? पीएम किसान निधि बिना ब्रेक के जारी है।" उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि आज तक पौने चार लाख करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के ढाई करोड़ किसानों को 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं, जबकि काशी के किसानों को 900 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई राजनेता और राजनीतिक दल है उसे संकोच को छोड़कर देशवासियों में इस भाव को जगाना होगा कि हम स्वदेशी का संकल्प लें। हमें उन चीजों को खरीदना चाहिए जिन्हें बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है।

## दुश्मन के घर में घुसकर खात्मा करने का माद्दा रखता है नया भारत: योगी

**वाराणसी/लखनऊ**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की शक्ति व सामर्थ्य का अहसास किया है। नया भारत पहलगाम के अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर और दुश्मन के घर में घुसकर उसका खात्मा करने का माद्दा रखता है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। पिछले 11 वर्ष में चार दर्जन से अधिक देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान समर्पित किया है। लोककल्याण और विश्वकल्याण के लिए दुनिया उनकी दूरदर्शिता का लोहा मानती है। जुलाई में घाना, त्रिनिदाद-टोबैगो, नामीबिया, ब्राजील ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ग्रामसभा-बनौली (कालिका धाम), सेवापुरी में आयोजित लोकार्पण/शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत पावन श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव के धाम और अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी का स्वागत-अभिनंदन किया।

**यह पहली बार हो रहा होगा, जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वीं बार हुए उपस्थित**

सीएम योगी ने कहा कि सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री संसद में इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि काशी की आत्मा सनातन और आत्मीयता वैश्विक है। काशी 11 वर्ष में नूतन व पुरातन के साथ आध्यात्मिकता व आधुनिकता के नए संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। यह पहली बार हो रहा होगा, जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वीं बार उपस्थित हुए होंगे।

**वाराणसी के लिए स्वीकृत हुई 51 हजार करोड़ की परियोजनाएं**

सीएम योगी ने बताया कि इन वर्षों में वाराणसी के लिए 51 हजार करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हुईं। इनमें से 34 हजार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण पीएम के करकमलों से हो गया है, जो समग्र विकास की नई अवधारणा के साथ काशी को पहचान दिला रहे हैं। 16 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं प्रगति के अलग-अलग चरणों में हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री 2200 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार अपनी काशी को दे रहे हैं। यह परियोजनाएं कनेक्टिविटी, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल प्रतिस्पर्धा-गतिविधि, सांस्कृतिक पुनरोत्थान के लिए है।

## पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सोने के बाघ की तरह दहाड़ रहा है भारत: मुख्यमंत्री मोहन यादव

**भोपाल**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बदलते दौर में भारत की भूमिका विश्व में निरंतर महत्वपूर्ण हो रही है। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भारत सोने के बाघ की तरह दहाड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 'भारत फर्स्ट' की भावना से देश के किसान और उद्योगपतियों के लिए दुनिया से लोहा लेने को तैयार हैं। उनकी मंशा के अनुरूप प्रदेश में हर दूसरे या तीसरे दिन उद्योगों को नई सौगात और युवाओं को रोजगार का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में सीहोर के बडियाखेड़ी में 2000 करोड़ रुपये

के निवेश से नए उद्योग आरंभ किए जाएंगे। सीहोर में जल्द ही एक लाख मैट्रिक टन सब्जियों की खरीद की व्यवस्था शुरू होगी, इससे जिले के दो लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। सीहोर में पावर ट्रांसफार्मर की इकाई लगने से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीहोर को "पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना" का लाभ भी मिलेगा। आगामी वर्षों में सीहोर, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को सीहोर जिले के बडियाखेड़ी में नई औद्योगिक इकाइयों के भूमि-पूजन और आशय-पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे।

## छात्र ही देश के सबसे बड़े भाग्यविधाता: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

**नई दिल्ली**

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के 39वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा केंद्र हमारे कॉलेज हैं और छात्र ही देश के सबसे बड़े भाग्यविधाता हैं। समारोह में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, विधायक कुलवंत राणा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों से शिक्षा की असली भावना को आत्मसात कर समाज और

राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि 140 करोड़ लोगों में से हर व्यक्ति अगर देश के लिए एक छोटा सा काम भी कर ले, तो भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने विचार, ऊर्जा और सहभागिता के माध्यम से देश की राजनीति और नीति-निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनें। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे दिल्ली सरकार के स्कूलों से जुड़ें और वहां पढ़ने वाले वंचित बच्चों के साथ संवाद करें। उन्होंने कहा कि जब आप जैसे छात्र झुग्गियों के बच्चों से जुड़ेंगे, तो उन्हें एक विजन, एक प्रेरणा मिलेगी। हम सब मिलकर तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपने पीछे वालों का हाथ पकड़ें। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अफसोस जताया कि पिछले 15 वर्षों में दिल्ली में एक भी नया कॉलेज नहीं खोला गया। इस कारण लाखों छात्रों को दिल्ली से बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब यह स्थिति बदलेगी।

## जलवायु परिवर्तन पर कोर्ट सख्त

## कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए ऊर्जा मंत्रालय को दिए निर्देश

**नई दिल्ली**

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिजली उत्पादन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए सभी संबंधित पक्षों को एक साझा मंच पर आना होगा। कोर्ट ने ऊर्जा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के साथ संयुक्त बैठक बुलाकर इस दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार करे। कोर्ट का मानना है कि नीति निर्धारकों को जमीनी वास्तविकताओं से जोड़े बिना उत्सर्जन की चुनौती को दूर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने 22 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि बिजली उत्पादन से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी स्टेकहोल्डर एक ही मंच पर आकर योजना बनाएं और उसे सुसंगत रूप से लागू करें। कोर्ट ने इस मुद्दे पर नीति बनाने वालों और क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता भी जताई। यह निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश से संबंधित है। एनजीटी ने पर्यावरण मंजूरी देने से पहले जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभावों का मूल्यांकन करने की मांग को लेकर आदेश पारित किया था। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीईए और सीईआरसी को मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया और ऊर्जा मंत्रालय को चार सप्ताह में योजना पर आधारित एक संयुक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 21 फरवरी 2025 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन अब एक वैश्विक संकट बन चुका है।

## दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर संवेदनशीलता की जरूरत: न्यायमूर्ति मनमोहन

**नई दिल्ली**

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन ने शनिवार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति मनमोहन 'न्यायिक दृष्टिकोण और वकालत के सीमांत क्षेत्रों में - दिव्यांग अधिकार और उससे आगे' विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। इस

सम्मेलन का आयोजन जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन ने क्यूएबल के सहयोग से किया।

**'जब समाज समझेगा, तो अदालतें भी बेहतर समझेंगी'**

न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि अदालतें दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़े मामलों में फैसले देती रही हैं और आगे भी देती रहेंगी, लेकिन यह जिम्मेदारी केवल न्यायपालिका की नहीं है, बल्कि राज्य के अन्य विभागों को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा, 'जरूरत है कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए, ताकि लोग कानून और दिव्यांगों के अधिकारों को समझें। जब समाज समझेगा, तो अदालतें भी बेहतर समझेंगी और फैसलों का पालन भी बेहतर होगा।'

## बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर, स्लीपर-थर्ड एसी में मिल सकती है किराये में छूट

**नई दिल्ली**

भारतीय रेलवे की ओर से एक बार फिर यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जल्द ही ट्रेन टिकटों पर फिर से किराया छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान बंद की गई यह सुविधा अब दोबारा बहाल हो सकती है, जिससे लाखों बुजुर्ग यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। हाल ही में राज्यसभा में कई सांसदों ने रेलवे मंत्रालय से सवाल पूछा था कि बुजुर्गों को दी जाने वाली रियायतें कब बहाल होंगी? इस पर मंत्रालय ने जवाब दिया कि रेलवे की स्थायी समिति ने बुजुर्गों के लिए फिर से रियायत बहाल करने की सिफारिश की है। समिति ने विशेष रूप से स्लीपर और थर्ड एसी क्लास में छूट पर दोबारा विचार करने को कहा है।

## हरियाणा के 16 लाख 77 हजार किसानों के खातों में पहुंचे 353 करोड़ रुपये

### जिला पंचकूला में पीएम किसान उत्सव दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की

**चंडीगढ़**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी उत्तर प्रदेश से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 9 करोड़ 70

लाख किसानों के खातों में 20वीं किस्त जारी कर 20 हजार 500 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया। इसमें हरियाणा के 16 लाख 77 हजार किसानों के खातों में 353 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है। इस उपलक्ष्य में शनिवार को जिला पंचकूला में पीएम किसान उत्सव दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अलावा, अन्य जिलों में भी पीएम किसान उत्सव दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट व राज्य मंत्रियों ने शिरकत की। कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दिए गए संबोधन को लाइव सुना गया।

अपने संबोधन में नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री द्वारा जारी 20वीं किस्त का वितरण केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि देश के किसानों को दिए गए भरोसे का प्रमाण है। यह उस संकल्प की पुनः पुष्टि है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अन्नदाता के कल्याण के लिए लिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके साथ, किसानों की आय में बढ़ोतरी, तकनीकी नवाचार और जल-संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी अनुकरणीय कार्य किए हैं। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र किसान इन योजनाओं से वंचित न रहे। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, कृषि विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

# वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 47वें नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला

एजेंसी

**नई दिल्ली।** वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 47वें नौसेना उप प्रमुख (वीसीएनएस) के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद साउथ ब्लॉक लॉन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गनरी और मिसाइल प्रणालियों के विशेषज्ञ संजय वात्स्यायन ने तीन दशकों से अधिक के अपने नौसैनिक करियर में विभिन्न प्रकार के कमांड, ऑपरेशनल और स्टाफ जिम्मेदारियां संभाली हैं। नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने एकीकृत रक्षा स्टाफ (डीसीआईडीएस) संचालन के उप प्रमुख और उसके बाद आईडीएस मुख्यालय में डीसीआईडीएस (नीति, योजना और बल विकास) के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने तीनों सेनाओं में संचालन के समन्वय, एकीकरण, संयुक्तता, बल विकास और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फरवरी, 2020 में उन्होंने पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला और गलवान? घाटी में चीन के साथ खूनी संघर्ष के बाद समुद्री गतिविधियों के दौरान कई ऑपरेशनल तैनाती और अभ्यासों का नेतृत्व किया। पुणे के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 71वें



पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को 01 जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था। फ्लैग ऑफिसर ने समुद्र में विभिन्न अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर सेवा की है, जिनमें गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मैसूर, आईएनएस निशंक के कमीशनिंग दल और तटरक्षक ओपीवी आईसीजीएस संग्राम के प्रीकमीशनिंग दल शामिल हैं। उन्होंने आईएनएस मैसूर के कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने तटरक्षक जहाज सी-05, मिसाइल पोत आईएनएस विभूति और आईएनएस नाशक, मिसाइल कार्वेट आईएनएस कुठार और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री (कमीशनिंग कमांडिंग ऑफिसर) की कमान संभाली है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, नेवल वॉर कॉलेज, गोवा और प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली से स्नातक, फ्लैग ऑफिसर ने प्रमुख रणनीतिक और नीति-उन्मुख स्टाफ भूमिकाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नौसेना मुख्यालय में उनकी नियुक्तियों में संयुक्त निदेशक और कार्मिक निदेशक (नीति), नौसेना योजना निदेशक (परिप्रेक्ष्य योजना) और प्रमुख नौसेना योजना निदेशक शामिल हैं। फरवरी, 2018 में फ्लैग रैंक पर पदोन्नति के बाद उन्होंने पूर्वी बेड़े की कमान संभालने से पहले सहायक नौसेनाध्यक्ष (नीति और योजना) के रूप में कार्य किया। नौसैनिक करियर में उनके असाधारण नेतृत्व और अत्यंत उच्च कोटि की सराहनीय सेवा के लिए उन्हें 2021 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

## यूपी को फुटवियर-लेदर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाएगी नई नीतिः मुख्यमंत्री

एजेंसी

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश ने फुटवियर, लेदर और नॉन-लेदर विनिर्माण के क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के पारंपरिक कौशल, प्रशिक्षित श्रमबल, कच्चे माल की प्रचुरता और आगरा, कानपुर व उन्नाव जैसे सशक्त औद्योगिक केंद्रों की मौजूदगी को देखते हुए एक समग्र, व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी नीति का निर्माण करना आवश्यक हो गया है। बैठक में 'उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर एवं नॉन-लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025' के प्रारूप पर विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने क्लस्टर आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि नीति में स्पष्ट रूप से यह परिभाषित किया जाए कि प्रदेश के कौन-से क्षेत्र इस उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि यदि उत्पादन, डिज़ाइन, अनुसंधान और प्रशिक्षण को एकीकृत किया जाए तो यह क्षेत्र न केवल बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित कर सकता है, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स जैसी अधोसंरचना सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया ताकि औद्योगिक इकाइयों को बेहतर कार्य वातावरण मिल सके। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रस्तावित नीति के तहत अगले कुछ वर्षों में लगभग 22 लाख नई नौकरियों के सृजन की संभावना है। यह नीति उत्तर प्रदेश को वैश्विक फुटवियर और लेदर विनिर्माण का केंद्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल मानी जा रही है। वर्तमान में भारत इस क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी महत्वपूर्ण है। अकेले कानपुर और उन्नाव में 200 से अधिक सक्रिय टैनरियां कार्यरत हैं। आगरा को तो देश की फुटवियर राजधानी के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति के तहत न केवल लेदर और नॉन-लेदर फुटवियर निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि इससे जुड़ी सहायक इकाइयों; जैसे बकल्स, ज़िप, सोल, इनसोल, लेस, केमिकल्स, डाइज, हील्स, थ्रेड्स, टैग्स और लेबल्स के निर्माण को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मशीनरी निर्माण, विशेष रूप से चमड़ा सिलाई, कटिंग, मोल्डिंग और नॉन-लेदर सेफ्टी शूज़ बनाने वाली तकनीकों से संबंधित इकाइयों को भी समर्थन मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समग्र दृष्टिकोण प्रदेश में एक पूर्ण एकीकृत फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करेगा, जिससे 'डिज़ाइन टू डिलीवरी' मॉडल को स्थानीय स्तर पर साकार किया जा सकेगा। उन्होंने बेहतर उत्पादों के लिए स्किलिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की मजबूत रणनीति तथा प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

## उमर को साबरमती रिवरफ्रंट पर दौड़ का आनंद लेते देखना अच्छा लगाः मोदी

**नई दिल्ली।)** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को साबरमती रिवरफ्रंट पर दौड़ का आनंद लेते और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाते देखकर अच्छा लगा। उनकी यह यात्रा एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है और हमारे साथी भारतीयों को भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर



कहा, 'श्री उमर अब्दुल्ला जी को साबरमती रिवरफ्रंट पर दौड़ का आनंद लेते और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाते देखकर अच्छा लगा। उनकी यह यात्रा एकता का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है और हमारे साथी भारतीयों को भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी।' इससे पूर्व उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट में केवडिया यात्रा के फोटो साझा करते हुये कहा, एक पर्यटन कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद में रहते हुए, मैंने यहाँ होने का लाभ उठाते हुए प्रसिद्ध साबरमती रिवरफ्रंट सैरगाह पर अपनी सुबह की दौड़ लगाई। यह उन सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जहाँ मैं दौड़ पाया हूँ और इतने सारे अन्य पैदल यात्रियों/धावकों के साथ इसे साझा करना मेरे लिए खुशी की बात थी। मैं अद्भुत अटल फुट ब्रिज के पास से भी दौड़कर गुज़रा।

## विपक्षी दलों ने बिहार मतदाता सूची मुद्दे पर ओम बिरला को लिखा पत्र

**नई दिल्ली।** इंडिया गठबंधन के विभिन्न दलों के नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा कराने का आग्रह करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण पर गहरी चिंता व्यक्त करते कहा है यह तब और भी चिंता का विषय बन जाता है जब राज्य विधानसभा चुनाव कुछ ही माह में होने वाले हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को अभूतपूर्व बताया और कहा कि चुनाव आयोग ने संकेत दिया है कि इस प्रकार की कवायद जल्द ही पूरे देश में की जाएगी। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया की पारदर्शिता, समय-सीमा और उद्देश्य को लेकर व्यापक आशंकाएं बन रही हैं इसलिए इस मुद्दे पर तत्काल संसद में चर्चा करना जरूरी है। विपक्षी दलों ने अपने पत्र में कहा कि विभिन्न दल लगातार इस मुद्दे को मौजूदा सत्र की शुरुआत से ही उठाते रहे हैं और सरकार के साथ कई बैठकों में भी इसी मुद्दे पर चिंता जताते हुए इसे दोहराया गया है।

# उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को

## नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त,चुनाव आयोग ने की घोषणा

एजेंसी

**नई दिल्ली ।** देश के अगले उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार, उपचुनाव 9 सितंबर को कराया जाएगा, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि नामांकन पत्रों की




जांच 22 अगस्त को की जाएगी। वहीं, नाम वापसी की आखिरी तारीख 25 अगस्त तय की गई है। यदि जरूरत पड़ी तो मतदान 9 सितंबर को होगा और इसी दिन मतगणना कर परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आयोजित कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव 'राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952' तथा 'राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974' के अंतर्गत संपन्न कराया जाता है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि वह स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं।16 जुलाई 2022 को भाजपा ने एनडीए की ओर से धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था। 6 अगस्त 2022 को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बड़े अंतर से हराया था।

## प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के विषयों के बारे में जनता से सुझाव किये आमंत्रित

एजेंसी

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीन से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के विषयों के बारे में जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि वह इस बारे में भारत के लोगों की राय जानने को उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर



एक पोस्ट में लिखा, हमारा स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, मैं अपने साथी भारतीयों से(उनके विचार) सुनने के लिए उत्सुक हूँ! उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन के विषयों के बारे में जनता से सुझाव मांगते हुए कहा पूछा है ,आप इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस भाषण में किन विषयों या विचारों को प्रतिबिंबित होते देखना चाहेंगे? देश स्वाधीनता की 78वीं वर्षगांठ की तैयारी में लग गया है। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह राजधानी में लाल किले पर आयोजित किया जाता है जहां प्रधानमंत्री सेनाओं की सलामी लेने के बाद लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। शाम को राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस मिलन समारोह आयोजित किया जाता है।

### मालेगांव ब्लास्ट केस : पूर्व एटीएस इंस्पेक्टर का दावा–

## आरएसएस प्रमुख भागवत की गिरफ्तारी का था दबाव, भगवा आतंकवाद साबित करने की थी साज़िश

एजेंसी

**नई दिल्ली।** मालेगांव ब्लास्ट केस में 31 जुलाई को आए NIA स्पेशल कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर सियासी भूचाल ला दिया है। सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद अब महाराष्ट्र ATS के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि उन पर RSS प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव डाला गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने के लिए इस तरह की साजिशें रची गईं। पूर्व इंस्पेक्टर मुजावर ने कहा, मेरे पास दस्तावेज हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मुझसे कहा गया था कि मैं मोहन भागवत को गिरफ्तार करूं। यह आदेश मुझे मौखिक रूप से भी दिए गए और दस्तावेज़ी रूप में भी। लेकिन मैं जानता था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया।

**भागवत की गिरफ्तारी मेरी क्षमता से बाहर थी**

मुजावर ने साफ शब्दों में कहा कि वे कभी भी इस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बने क्योंकि उन्हें शुरू से ही पता था कि ये सारी चीजें गढ़ी जा रही हैं। ÷कोई भगवा आतंकवाद नहीं था। यह सब फर्जी था। मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना मेरी हैसियत और नैतिकता दोनों से बाहर था,' उन्होंने कहा।

**फैसले ने उजागर कर दी फर्जी जांच**

31 जुलाई को जब NIA की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, तो मुजावर ने इस फैसले को 'फर्जी अधिकारी की फर्जी जांच का पर्दाफाश' करार दिया। उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कह सकता कि ATS ने क्या और क्यों जांच की, लेकिन मेरे पास जो गोपनीय आदेश दिए गए थे उनमें राम कलसांगरा, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार और यहां तक कि मोहन भागवत का नाम भी शामिल था।

**मालेगांव धमाके की पृष्ठभूमि :** मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। शुरुआती जांच महाराष्ट्र ATS ने की, जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया। बाद में 2011 में यह केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपा गया। अब 16 साल बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

## सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न विरोधी कानून के दायरे में लाने की याचिका खारिज की

एजेंसी

**नई दिल्ली ।** उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश अधिनियम) के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह विषय संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने अधिवक्ता योगमाया एम जी की इस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। पीठ ने कहा याचिकाकर्ता से कहा कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता को सुझाव दिया कि वे कुछ महिला सांसदों को शामिल कर इस संबंध में एक निजी विधेयक



पारित करने की दिशा में प्रयास करें। इस पर अधिवक्ता गुप्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कोई अधिनियम नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों को पोश अधिनियम के दायरे में लाने के लिए अदालत की व्याख्या चाहती हैं। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पोश अधिनियम के अर्थ में राजनीतिक दल 'कार्यस्थल' और 'नियोक्ता' माने जाएँगे, इसलिए उन्हें महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं के यौन उत्पीड़न से निपटने के प्रावधानों का पालन करना होगा।उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के 2021 के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पोश अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता ने मामला वापस लेने का विकल्प चुना। शीर्ष अदालत ने 09 दिसंबर, 2024 को याचिकाकर्ता द्वारा दायर इसी तरह की एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

## रेप केस में पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करारः सजा का ऐलान आज

एजेंसी

**बेंगलुरु।** कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व छ्ठ्ठस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को एक महिला कर्मचारी से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत शनिवार को सजा की घोषणा करेगी।फैसला सुनते वक्त रेवन्ना बेहद भावुक नजर आया और कोर्ट से बाहर निकलते समय फफक कर रो पड़ा। यह मामला 2023 में दर्ज हुआ था, जब एक 47 वर्षीय महिला ने रेवन्ना पर लगातार यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। महिला रेवन्ना के पारिवारिक फार्महाउस में मेड के तौर पर कार्यरत थी और उसने बताया कि 2021 से उसका यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। साथ ही, घटना की जानकारी देने पर अश्लील वीडियो लीक करने की धमकी भी दी जाती थी। कोर्ट ने इस केस में



बलात्कार, आपराधिक धमकी, ताक-झांक और अश्लील सामग्री प्रसारित करने जैसी धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। 18 जुलाई को मामले की अंतिम सुनवाई पूरी हुई थी। यह केस प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज चार आपराधिक मामलों में से पहला है, जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। उल्लेखनीय है कि रेवन्ना का नाम पिछले साल सामने आए कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में भी प्रमुख रूप से उभरा था, जहां उस पर 50 से अधिक महिलाओं के यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे थे। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स से करीब 2,000 अश्लील वीडियो क्लिप्स भी सामने आए थे, जिससे यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में रेवन्ना ने हासन सीट से दोबारा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। विवादों के बाद छ्ठ्ठस पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।

## नीतीश की एक और सौगात, शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, मिड डे मील रसोइयों और नाइट वॉचमैन के मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी

एजेंसी

**पटना।** मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे चुनावी मोड में चल रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार उन्होंने शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रूपये से 3300 रूपये किए जाने की घोषणा की। अपने एक्स हैंडिल से उन्होंने पोस्ट कर बताया है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए इन कर्मियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रूपये से 3300 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। वहीं माध्यमिक/उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रूपये से दोगुना करते हुए इसे अब 10000 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8 हजार रूपये से दोगुना करते हुए अब 16 हजार रूपये करने का निर्णय लिया गया है।

## चुनाव आयोग करवाता है वोट चोरी, हमारे पास हैं सबूत : राहुल

एजेंसी

**नई दिल्ली ।** कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है और इसके उनके पास पर्याप्त सबूत हैं लेकिन जो यह चोरी करवा रहे हैं उनका यह काम देशद्रोह हैं और ऐसे लोगों को खोज निकालेंगे। श्री गांधी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। मैं शत- प्रतिशत सबूतों के साथ ये बात कह रहा हूं। हम जैसे ही ये सबूत सबके सामने रखेंगे, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है। कांग्रेस



नेता ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि चुनाव आयोग यह काम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए करा रहा है। उन्होंने कहा कि सवाल है कि आयोग किसके लिए करा रहा है यह वोट चोरी, इसका जवाब है कि भाजपा के लिए करा रहा है।उन्होंने कहा, हमें मध्य प्रदेश में संदेह था, लोकसभा चुनाव में संदेह था, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संदेह था। चुनाव आयोग हमारी मदद नहीं कर रहा था इसलिए हमने अपनी तरफ से जांच करवाई। इस जांच में छह महीने लगे और जो हमें मिला है- वह एटम बम है। चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो देशद्रोह है। आप कहीं भी हों, चाहे आप रिटायर ही क्यों न हो जाएं, हम आपको ढूंढ निकालेंगे।

## प्रेमचंद की विरासत व्यापक और बहुआयामी : श्यौराज सिंह

एजेंसी

**नई दिल्ली।** साहित्य अकादमी ने प्रेमचंद जयंती पर प्रेमचंद की विरासत और वर्तमान कथा परिदृश्य विषयक चर्चा का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रख्यात लेखक श्यौराज सिंह 'बेचैन' ने प्रेमचंद की विरासत को व्यापक और बहुआयामी बताते हुए कहा कि लेखक का काम दर्पण दिखाना होता है, वह प्रेमचंद ने बहुत ईमानदारी से किया। श्यौराज सिंह ने यहां के फिरोजशाह रोड स्थित साहित्य अकादमी के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रेमचंद के दलित चरित्रों के चित्रण पर अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रेमचंद दलितों के जीवन की त्रासदी तो बहुत सच्चाई से रखते हैं, लेकिन उनका कोई भी चरित्र इसका कोई बहुत विरोध करता नहीं दिखाई देता। इस संदर्भ में उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसा इसलिए भी है कि लेखक का दायित्व सच्चाई को प्रकट करना है और परिवर्तन का काम उस समाज को करना होता है। उन्होंने प्रेमचंद के संघर्षपूर्ण जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत जोखिम लेकर समाज की सच्चाई सामने रखा। वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार राय ने प्रेमचंद के जीवन और लेखन से कई उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी विरासत अनमोल है और नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम के बाद सवाल-जवाब के क्रम में कहानीकार राजकुमार गौतम ने प्रेमचंद की विरासत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को केवल उनके लेखन से नहीं बल्कि उनके जीवन संघर्षों और उच्च लक्ष्यों के प्रति उनकी निष्ठा को भी समझना और अपनाना होगा।

## सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कई निर्णय : रेखा गुप्ता

**नई दिल्ली।** दिल्ली में विकास कार्यों की गति बढ़ाने, उसमें अधिक पारदर्शिता लाने और आर्थिक व्यवधान को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर कई आवश्यक बदलाव व महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यह जानकारी रविवार को एक विज्ञप्ति करते हुए दी। मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ): मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस निधि का उद्देश्य दिल्ली के बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना को 2025-26 में लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के योजना विभाग को 1400 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन विधायकों को अपने क्षेत्र में किसी विकास कार्य के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी, वह अब इस निधि से राशि ले सकते हैं। एक प्रोजेक्ट की अधिकतम लागत 10 करोड़ रुपये तय की गई है। यह योजना स्थानीय स्तर पर विकास के लिए लचीला और गतिशील तंत्र प्रदान करेगी। इसकी विशेषता यह भी है कि प्रशासनिक विभाग, स्थानीय निकाय और स्वायत्त संस्थाएं (अपने प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से) परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगी, जो दिल्ली मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आधारित होंगे। बड़ी बात यह भी है कि योजना विभाग प्रोजेक्ट की कुल राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम देगा और शेष 50 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा। यह भुगतान कार्य की प्रगति, उपयोग प्रमाणपत्र और पूर्णता प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित विभाग या एजेंसी को किया जाएगा।

## 'भारत गौरव रत्न श्री सम्मान' समारोह में समाज सेवा के नायकों का सम्मान

**नई दिल्ली।** 'भारत गौरव रत्न श्री सम्मान' समारोह द अशोक होटल चाणक्यपुरी नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले असली नायकों को राष्ट्रीय मंच से सम्मानित करना रहा। इस समारोह में देशभर के 150 से अधिक समाजसेवियों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों एवं जमीनी बदलाव लाने वाले व्यक्तित्वों ने भाग लिया। समारोह में असम, नागालैंड एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी, अभिनेत्री नुसरत भरूचा विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने देशभर से चयनित कर्मयोद्धाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बिहार से डॉ. भीमराज प्रसाद (गया) एवं डॉ. अमरदीप कुमार (मधेपुरा) को एचडीएसी संस्था के राष्ट्रीय सदस्य एवं उपाध्यक्ष के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा हेतु सम्मान मिला। वहीं महाराष्ट्र से डॉ. कविता सोनी (मुंबई) को मानसिक स्वास्थ्य में योगदान हेतु एचडीएसी की ओर से राष्ट्रीय सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया।

## हंसराज कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन, शुरू होगा नया सत्र

**नई दिल्ली।** दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में शुक्रवार से शुरू हो रहे नए सत्र के विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कॉलेज के इतिहास, परंपरा के साथ ही यहां संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों और उसके विविध पक्षों से परिचित कराया गया। यह जानकारी कॉलेज ने एक बयान में दी। कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रमा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नए वर्ष के विद्यार्थियों को कॉलेज जीवन के महत्व, उसके सार्थक उपयोग, दृष्टि निर्माण के लिए जरूरी तत्वों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, मर्यादा और जीवन जीने की कला के साथ अकादमिक उत्कर्ष के लिए सतत सचेत रहने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करने का आह्वान किया।

# हिंदू-मुस्लिम के बीच खाई को पाटने के एमआरएम का मुस्लिम मीडिया ग्रुप के साथ संवाद

एजेंसी

**नई दिल्ली।** मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और मुस्लिम मीडिया ग्रुप के बीच दिल्ली के हरियाणा भवन में 'संवाद से समाधान' विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच व्याप्त नफरत की खाई को पाटने के विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डॉ इंद्रेश कुमार, संयोजक डॉ शाहिद अख्तर और मीडिया कोऑर्डिनेटर शाहिद सईद ने भाग लिया। दूसरी तरफ मीडिया समूह के पत्रकारों और संपादकों ने भी भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए डॉ इंद्रेश कुमार ने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा कर करके उन्हें बांटने की जो साजिश रची थी, उसका परिणाम विभाजन के रूप में सामने आया, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आज तक

अंग्रेजों की इस फूट डालो नीति का असर हमें देखने को मिल रहा है। छोटी-छोटी बातों पर आपस में हिंदू-मुसलमानों के बीच तनाव उत्पन्न होने की खबरें हमेशा आती रहती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा गौ हत्या को लेकर है। हमारे देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इस पर सभी सहमत हैं लेकिन कभी-कभी इस तरह की वारदात हो जाती है जिसको लेकर लिंचिंग की घटनाएं सामने आती हैं जो हमारे समाज का भयानक रूप सामने लाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में राष्ट्रीयता की कमी है जो अक्सर हमें देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि पुलवामा, पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना पर भी हम एक स्वर होकर इसका विरोध नहीं कर पाए। उन्होंने कल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे देश पर टैरिफ लगाया गया लेकिन हम इस पर भी एक मत नहीं हो पाए और एकजुट होकर यह नहीं कह पाए की यह हमारे राष्ट्र का मामला है, इसे हम सब मिलकर के हल करेंगे। बैठक में कई पत्रकारों के जरिए उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के जरिए किए जाने वाले उत्पात, मोहर्रम के जुलूस को लेकर की जाने वाली टिप्पणी और सरकारी भेदभाव का मामला भी उठाया गया। उर्दू अखबारों की दयनीय स्थित और सरकार की उदासीनता पर भी सवाल किए गए ।

## संसद ने की निसार उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किए जाने पर वैज्ञानिकों की प्रशंसा

एजेंसी

**नई दिल्ली।** लोकसभा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त प्रयास के तहत जीएसएलवी रॉकेट से नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किए जाने को लेकर वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन समवेत होते ही इस बारे में सदस्यों को सूचित करते हुए कहा बुधवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी-एफ16 रॉकेट के माध्यम से नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा यह अपनी तरह का पहला संयुक्त मिशन है, जिसे सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। 'माइक्रोवेव इमेजिंग' तकनीक पर आधारित यह उपग्रह वैश्विक भू-पारिस्थितिकी तंत्र एवं समुद्री क्षेत्रों के अध्ययन में सहायक सिद्ध होगा। श्री बिरला ने कहा हमें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सफलता पर गर्व है और उनके भावी अंतरिक्ष अभियानों की सफलता की कामना करते हैं। यह उपलब्धि देश के वैज्ञानिक सामर्थ्य का प्रतीक है, जो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। राज्यसभा में सुबह पहले सदन में कार्यवाही शुरू होते ही सदन ने भारत और अमेरिका के संयुक्त अभियान के तहत प्रक्षेपित निसार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी। उप सभापति हरिवंश ने सदन को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अमेरिकी अंतरिक्ष विभाग (नासा ) ने मिलकर हासिल की है।

# देश को आर्थिक असमानता और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से निपटना होगा : प्रियंका चतुर्वेदी

एजेंसी

**नई दिल्ली।** शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत निस्संदेह कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ प्वाइंट रखें। चतुर्वेदी ने अपने बयान में रेखांकित किया कि भारत को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, धन की असमानता को कम करने, किसानों और व्यवसायों की चिंताओं को संबोधित करने, और बेरोजगारी की समस्या से निपटने की जरूरत है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हां, भारत के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं। भारत को प्रति व्यक्ति आय पर काम करना है। भारत को धन की असमानता को दूर करना है। भारत को किसानों और व्यापारियों की चिंताओं को समझना है। भारत को बेरोजगारी की समस्या से निपटना है, लेकिन सारी आर्थिक चुनौतियों का मतलब यह नहीं कि

हमारी अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है। यह साफ तौर पर एक बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात है, शायद किसी सौदे को पूरा करने के लिए। चतुर्वेदी का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग उनकी राय के समर्थन में दिखे, जबकि कुछ लोगों ने उनके बयान पर असहमति जताई। प्रियंका चतुर्वेदी ने ये बयान उस समय दिया है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से होने वाले आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ और अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला 1 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप के इस फैसले पर देश में राजनीति तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत पर 25 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ के बाद सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को देश चलाना नहीं आता है। इस सरकार ने देश की पूरी इकॉनमी को खत्म कर दिया है।

## पीएम मोदी ने प्रमिला ताई मेढ़े के निधन पर जताया दुख, कहा- हमेशा याद रहेगा उनका योगदान

एजेंसी

**नई दिल्ली ।** राष्ट्र सेविका समिति की पूर्व प्रमुख संचालिका प्रमिला ताई मेढ़े का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में उनके अमूल्य योगदान को सदैव याद किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका रहीं श्रद्धेय प्रमिला ताई मेढ़े के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। उनका संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र सेवा को समर्पित रहा। महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में उनके अमूल्य योगदान को सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों को संबल प्रदान करे। ओम शांति! केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रमिला ताई मेढ़े के निधन पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख संचालिका श्रद्धेय प्रमिला ताई मेढ़े का निधन सभी समाजसेवियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है।

दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। प्रमिला ताई आजीवन राष्ट्रसेवा और नारी शक्ति के सशक्तीकरण हेतु समर्पित रहीं। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय सेविका समिति जनकल्याण का पर्याय बनीं। उनके सेवा कार्य और समाज के उत्थान का संकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणीय हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रमिला ताई मेढ़े को श्रद्धांजलि अर्पित की। संघ के आधिकारिक एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई, जिसमें मोहन भागवत उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा, राष्ट्र सेविका समिति की भूतपूर्व प्रमुख संचालिका प्रमिला ताई मेढ़े के परलोक गमन से हम सभी लोगों के सर पर से एक मातृवत छत्र हट गया है। उनके निधन से लगभग समिति की स्थापना काल से आज तक की उनकी दीर्घ तपस्या की पूर्णता हो गई है। लक्ष्य की अचूक समझ व निष्ठा, कार्य वृद्धि के लिए सातत्यपूर्ण कठोर परिश्रम तथा व्यवहार में आत्मीयता का वे मूर्तीमंत उदाहरण थीं। राष्ट्र सेविका समिति के कार्ययज्ञ में अपनी जीवन समिधा अर्पित कर अंततोगत्वा उन्होंने मरणोपरांत देहदान संकल्प से अपने देह का भी समर्पण कर दिया। उनकी तपस्या के कारण उनकी सद्गति तो सुनिश्चित है। उनके बिना ध्येय पथ पर आगे बढ़ने का धैर्य हम सभी को मिले, यही ईश चरणों में प्रार्थना।

# भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में अलग-थलग पड़े राहुल

एजेंसी

**नई दिल्ली।** लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी अनेक बार भारत के लिए शर्मिंदगी का कारण बनते रहे हैं। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रम्प के भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में दिए गए बयान पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया से उनकी नासमझी और मोदीविरोध से बढ़कर भारतविरोधी सोच सामने आई है। अमेरिका और भारत के बीच लंबे समय से व्यापारिक समझौते (ट्रेड डील) पर गतिरोध बना हुआ था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि वह भारत के लिए हो रहे निर्यातों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे। इससे भारत के व्यापार और आर्थिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह अलग विषय है, लेकिन इसकी घोषणा करते समय कुछ चिड़चिड़े भाव से ट्रम्प ने भारत की इकॉनमी को 'डेड इकॉनमी' बताया। यह एक प्रकार से अमेरिकी शर्तें न मानने से

उपजा गुस्सा था। पर गजब ये कि भारत में नेता प्रतिपक्ष ने तुरंत इसे लपक लिया और ट्रम्प के सुर में सुर मिलाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को मृत करार दे दिया। ट्रम्प के बयान पर प्रतिक्रिया लेने पहुंचे पत्रकारों को संसद भवन परिसर में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो कहा, वह न केवल तथ्य और सत्य से परे है, बल्कि देश के विरोध में भी है। राहुल गांधी ने कहा, ''ट्रम्प बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह सभी को पता है सिर्फ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने तथ्य बताया है।'' इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भारत की डेड हो रही इकॉनमी के लिए अडानी को जिम्मेदार बताया। किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति की भारतविरोधी टिप्पणी को लपक लेने वाले राहुल गांधी के इस बयान का चौतरफा विरोध सामने आने लगा है। खुद उनकी पार्टी कांग्रेस के नेता भी अपने नेता के बयान से सहमत नहीं हैं और साफतौर पर अलग राय व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राजीव शुक्ल ने तो साफतौर पर ट्रम्प के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। राजीव शुक्ला ने कहा, ''ट्रम्प का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है...हमने जो आर्थिक सुधार किए हैं, जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी थे और उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को वाजपेयी जी ने भी आगे बढ़ाया...फिर 10 साल मनमोहन सिंह जी ने मजबूती प्रदान की और उसके बाद फिर मौजूदा सरकार ने उसमें जो काम बढ़ाया... तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है...इसलिए कोई आर्थिक रूप से कहे कि हमें खत्म कर देगा तो उसकी गलतफहमी है। ट्रम्प गलतफहमी में जी रहे हैं।''

## एमसीडी स्कूलों के जर्जर भवनों को लेकर देवेंद्र यादव ने लिखा उपराज्यपाल और महापौर को पत्र

**नई दिल्ली।** दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के स्कूलों के जर्जर भवनों को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और महापौर को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने निगम स्कूलों की ढांचागत हालात को सुधारने के लिए उपराज्यपाल और महापौर से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। देवेंद्र यादव ने पत्र के माध्यम से बताया कि 30 से 50 वर्ष पुराने भवनों में चल रहे निगम के 1185 स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 7.8 लाख छात्रों का जीवन संकट में है। 16 जुलाई को स्थाई समिति की बैठक में स्कूलों की जर्जर हालत और स्कूल भवनों में पानी भरने का मामला उठाया गया परंतु कोई ठोस निर्णय निर्णय सामने नहीं आया। इस वर्ष निगम स्कूलों के लिए 1693 करोड़ से अधिक बजट का प्रावधान है, जो पिछले वर्ष के बजट से 48.2 करोड़ अधिक है। दिल्ली नगर निगम 1185 स्कूलों में 368 स्कूल जर्जर हालत में है और बाकि स्कूलों में भी उपयुक्त रखरखाव और मरम्मत की जरुरत है। निगम के 12 जोन में चलने वाले एक भी स्कूल के भवन की मरम्मत के लिए कोई काम क्यों नही हुआ। जहां पहाड़गंज जोन के 75 स्कूलों में 26 भवन जर्जर हालते है, वहीं करोलबाग जोन के 69 स्कूलों में 23 भवन जर्जर, केशव पुरम जोन के 89 स्कूलों में 35 भवन जर्जर, शाहदरा साउथ जोन के 127 स्कूलों में 33 भवन जर्जर शाहदरा नार्थ जोन के 103 स्कूलों में 14 भवन जर्जर, रोहिणी जोन के 80 स्कूलों में 23 भवन जर्जर, नजफगढ़ जोन के 110 स्कूलों में 36 भवन जर्जर, नरेला जोन के 145 स्कूलों में 26 भवन जर्जर सिविल लाइन जोन के 71 स्कूलों में 09 भवन जर्जर, सेंट्रल जोन के 94 स्कूलों में 53 भवन जर्जर, साउथ जोन के 120 स्कूलों में 59 भवन जर्जर और वेस्ट जोन के 102 स्कूलों में 31 भवन पूरी तरह जर्जर हालत में है।

## नौसेना की पश्चिमी कमान के कमांडर बने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, कार्यभार संभाला

एजेंसी

**नई दिल्ली ।** वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने युद्धपोत शिकरा पर एक औपचारिक परेड में वाइस एडमिरल संजय जे. सिंह से चार्ज लिया। अभी तक वह नई दिल्ली मुख्यालय में नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। कार्यभार ग्रहण करने पर वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई में 'गौरव स्तंभ' पर राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 01 जुलाई?, 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त? किया था। स्वामिनाथन फ्लैग ऑफिसर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (खड़कवासला), संयुक्त सेवा कमान एवं स्टाफ कॉलेज (श्रीवेनहम, यूनाइटेड किंगडम), नौसेना युद्ध महाविद्यालय (करंजा) और संयुक्त राज्य नौसेना युद्ध महाविद्यालय (न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड, अमेरिका) के छात्र रहे हैं।? उन्होंने अपने नौसैनिक करियर में कई प्रमुख परिचालन, स्टाफ और प्रशिक्षण पदों पर कार्य किया है, जिनमें मिसाइल पोत आईएनएस विद्युत और आईएनएस विनाश, मिसाइल कार्वेट आईएनएस कुलिश, निर्देशित

मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मैसूर और विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की कमान शामिल है। अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित फ्लैग ऑफिसर स्वामिनाथन ने नेरियर एडमिरल के पद पर पदोन्नति के बाद दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि मुख्यालय में मुख्य स्टाफ अधिकारी (प्रशिक्षण) के रूप में कार्य किया और भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय नौसेना सुरक्षा दल के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो नौसेना के सभी कार्यक्षेत्रों में परिचालन सुरक्षा की देखरेख करता है। इसके बाद उन्होंने फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग के रूप में नौसेना के वर्क-अप संगठन का नेतृत्व किया, जिसके बाद उन्हें पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में नियुक्त किया गया। स्वॉर्ड आर्म की कमान संभालने के बाद उन्हें भारत सरकार के अपतटीय रक्षा सलाहकार समूह के फ्लैग ऑफिसर और अपतटीय सुरक्षा एवं रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया।

## सर्वोदय विद्यालय में प्लेसमेंट ड्राइव व रोजगार मेले का आयोजन

एजेंसी

**नई दिल्ली।** दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-3 स्थित सर्वोदय विद्यालय में प्लेसमेंट ड्राइव व रोजगार मेले का आयोजन किया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद इस आयोजन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्लेसमेंट ड्राइव व रोजगार मेले में युवा प्रतिभाओं को विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद करने और रोजगार के अवसर प्राप्त करने का अवसर मिला। यह जानकारी शिक्षा मंत्री अपने एक्स काउंट पर साझा की है।शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य न केवल रोजगार उपलब्ध कराना था, बल्कि युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप सही दिशा देना भी था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार युवाओं के सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास कर रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

## प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों से मिले मुख्यमंत्री डॉ. यादव, मप्र सरकार की उपलब्धियों की दी जानकारी

एजेंसी

**भोपाल ।** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने पुष्प-गुच्छ भेंट कर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश की उपलब्धियों एवं नवाचार पर केंद्रित पुस्तिका ÷विरासत से विकास की राह÷ भेंट की। पुस्तिका में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन, जनजाति कल्याण, किसान कल्याण, नारी शक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, शहरी विकास, अधोसंरचना विकास, पर्यटन एवं संस्कृति संरक्षण और पर्यावरण संबंधी गतिविधियों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हाल ही में मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए की गई दुबई एवं स्पेन की यात्रा में मिली सफलता की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदेश की

साढ़े 8 करोड़ आबादी को हमेशा मिलता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से विकसित भारत ञ 2047 के विजन में मध्य प्रदेश भी अपना पूरा योगदान देगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गृह मंत्री शाह से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और दुग्ध-सहकारिता गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी भेंट कर प्रदेश में ऊर्जा, नगरीय विकास क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर नई शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन सहित पाठ्यक्रमों में राष्ट्रभक्तों और महापुरूषों की जीवनियों के शामिल किए जाने संबंधी प्रगति की जानकारी दी।

# बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चर्चा के लिए अड़ा विपक्ष, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित

एजेंसी

**नई दिल्ली।** राज्यसभा में विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया जिसके कारण तीन बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। तीसरे स्थगन के बाद जब सदन साढे चार बजे पुनः समवेत हुआ तो उप सभापति हरिवंश ने अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाये गये आयात शुल्क और रूस से हथियार तथा तेल खरीदने पर लगाये गये दंडात्मक शुल्क के संबंध में वक्तव्य देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का नाम पुकारा। श्री गोयल के खड़े होते ही विपक्ष के सदस्य अपनी जगहों से उठकर आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। केन्द्रीय मंत्री ने हंगामे के बीच ही अपना वक्तव्य सदन में रखा। उनका वक्तव्य समाप्त होने के बाद भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे जिसे देखते हुए उप सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह विपक्षी दलों ने ओड़िशा में महिलाओं के खिलाफ बढती अपराध की घटनाओं , बंगाली आव्रजक श्रमिकों के साथ दूसरे राज्यों में भेदभाव , छत्तीसगढ में दो नन की गिरफ्तारी और अमेरिका द्वारा भारत पर लगाये गये शुल्क तथा जुर्माने के मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नियम 267 के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिये थे। उप सभापति ने इन्हें नियमों के विरूद्ध बताते हुए स्वीकार नहीं किया था। विपक्ष के अपनी मांग पर अड़े रहने के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी थी। इसके बाद जब दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर से शोर शराबा शुरू कर दिया जिसे देखते हुए उप सभापति ने सदन की कार्यवाही साढे चार बजे तक स्थगित कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण मानसून सत्र के पिछले नौ दिनों में बमुश्किल तीन दिन ही विधायी कामकाज हो सका है। इसमें से एक दिन सरकार ने हंगामे के बीच एक विधेयक पारित कराया जबकि दो दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। बाकी के दिनों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बने गतिरोध के कारण विधायी कामकाज नहीं हो सका। उप सभापति हरिवंश ने सुबह कार्यवाही शुरू करने से पहले सदस्यों से सदन में शांति बनाए रखने का अनुरोध करते हुए कहा था कि मानसून सत्र में अब तक 30 घंटे का समय बर्बाद हो चुका है और यह सदस्यों का समय था।

## संपादक की कलम से

### गुजरात मॉडल ढह गया!

बड़े जोर-शोर के साथ विकास का बहुप्रचारित गुजरात मॉडल दिन-ब-दिन ढह रहा है। पहलगाम से लेकर दिल्ली तक, यह ढहना जारी है, लेकिन इस मॉडल की कमजोरी गुजरात में ही सामने आई है। कल, भारत ने वडोदरा-आणंद को जोड़ने वाले पुल के ढहने की लाइव तस्वीर देखी। इस पुल हादसे में ट्रक, टैंकर, कारें बह गईं और दस से ज्यादा लोग बह गए। मोरबी पुल से वडोदरा तक पुल का ढहना और बहना जारी है। मानो इतना ही काफी नहीं था, इसी बीच अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। २४३ लोग मारे गए। अब, जबकि गुजरात के सुपुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भ्रमण पर थे, तभी वडोदरा में पुल ढह गया। नरेंद्र मोदी कल तक इसी वडोदरा संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे। अब वे वाराणसी से सांसद हैं। उस वाराणसी की सड़कों में भी कुएं जितने गड्ढे हैं। मोदी गुजरात मॉडल का सपना दिखाकर वाराणसी में जीते थे। इस सपने की धज्जियां खुद गुजरात में ही उड़ गईं। महिसागर नदी पर बना पुल ढह गया। इस बात पर खूब चर्चा हो रही है कि यह पुल पुराना था। अगर पुल पुराना था तो फिर इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? अगर यह बहुत पुराना था, तो नया पुल क्यों नहीं बनाया गया? क्या गुजरात मॉडल वाले यह नहीं समझते कि इस हादसे में निर्दोष लोग मारे गए? यह गुजरात सरकार की कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। सरकार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि राज्य का सबसे ऊंचा पुल दो टुकड़ों में टूटने जितना खतरनाक हो गया था या फिर इस बात का अंदाजा होने के बावजूद लापरवाही

बरती गई। अगर अंदाजा होता, तो पुल पर यातायात बंद कर दिया जाता। लेकिन चूंकि वहां की पूरी सरकार गुजरात मॉडल के भरोसे पर चल रही थी, इसलिए यातायात जारी रहा और बुधवार को पुल के साथ यह भरोसा भी टूट गया। भले ही मान लिया जाए कि दुर्घटनाएं बोलकर नहीं होती, लेकिन यह तो एक तरह से पल्ला झाड़ना है। स्थानीय विधायक को अंदाजा था कि जो पुल दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वह पिछले कुछ सालों में कमजोर हो गया था और इस पर आवाजाही खतरनाक हो सकती है। इसके लिए एक नए पुल की मांग भी की गई थी। सरकार का कहना है कि उसने नए पुल के लिए २१२ करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर कर दिया है और एक सर्वेक्षण भी हो चुका है। तो अगर यह सब हुआ था, तो घोड़े कहां अटके थे? प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात मॉडल की अनगिनत परिकथाएं पिछले ढाई दशकों से रंगाकर सुनाई जाती रही हैं। बुधवार के पुल हादसे ने उन परिकथाओं के रंगों को एक बार फिर से कुरेद दिया। तीन साल पहले गुजरात के ही मोरबी में हुए भीषण पुल हादसे ने गुजरात मॉडल की पोल खोल दी थी। उस समय हुक्मरानों ने हादसे का ठीकरा पुल का रखरखाव और मरम्मत करने वाली कंपनी के माथे फोड़ दिया था और पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। मोरबी पुल हादसे में १४१ से ज्यादा निर्दोष लोगों की मौत

हो गई थी। वह पुल १४० साल पुराना था। अब ढहा हुआ गंभीरा पुल केवल ४५ साल पुराना था, लेकिन यह दो टुकड़ों में ढह गया। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया मोरबी हिलता पुल १४० साल तक चला। मोदी के तथाकथित गुजरात मॉडल द्वारा बनाया गया गंभीरा पुल के ४५ साल में ही दो टुकड़े हो गए! यह पाप केवल उन लोगों के लिए है जो गुजरात मॉडल के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं। आपके २१२ करोड़ रुपए के प्रावधान और सर्वेक्षण का क्या फायदा? यदि गुजरात मॉडल दूसरों से अलग होता, तो यह कमजोर पुल प्रावधान और सर्वेक्षण के कागजी घोड़े में नहीं फंसता और निर्दोष लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। वही सरकारी उदासीनता जिसके कारण पिछले महीने पुणे जिले में कुंडमाला पुल ढह गया, वही सरकारी उदासीनता है जिसके कारण तीन साल पहले गुजरात में मोरबी चल पुल दुर्घटना हुई और अब वडोदरा में गंभीरा पुल ढह गया। गुजरात मॉडल के पांव भी मिट्टी के निकले। प. बंगाल में एक पुल गिरने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने संभावना व्यक्त करते कहा था कि यह हादसा ऐक्ट आफ प्रष्ठाड है। तो बुधवार को उनके ही गुजरात में हुए पुल हादसे पर मोदी का क्या कहना है? क्या मोदी यह कहने की हिम्मत करेंगे कि यह भी ऐक्ट ऑफ प्रष्ठॉड है? मोदीजी, आपका गुजरात मॉडल भी गंभीरा पुल जितना ही कमजोर निकला है। अब तो मान लीजिए कि यह पुल नहीं, बल्कि गुजरात मॉडल ढहा है!

### तौलिया-बनियान गैंग

महाराष्ट्र में कानून का राज नहीं रहा है। फडणवीस सरकार का समर्थन करनेवाले विधायक संजय गायकवाड ने जिस तरह से विधायक निवास की कैंटीन के कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई की, वह धक्कादायक है। विधायक गायकवाड पचास खोके वाले विधायक हैं। फिर भी वह विधायक निवास में रहते हैं। मंगलवार की रात, विधायक ने अपने कमरे में कैंटीन से दाल-भात और चपाती जैसा साधारण मेनू ऑर्डर किया। उन्होंने महसूस किया कि यह भोजन विधायकों के खाने लायक नहीं था। इस कैंटीन में सुबह से सैकड़ों लोगों ने उस भोजन का स्वाद चखा होगा, लेकिन विधायक को यह पच नहीं पाया। उनका कहना था कि दाल खराब थी और बदबू आ रही थी। विधायक निवास की कैंटीन सरकारी सब्सिडी के कारण सस्ता भोजन प्रदान करती है और कई लोग इसका लाभ उठाते हैं। उनमें अन्य विधायक, राजनीतिक कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी भी हैं, लेकिन विधायकों की घ्राणेंद्रिय दूसरों की तुलना में तेज और जीभ तीखी होती होगी इसलिए कैंटीन का खाना अच्छा नहीं है, इससे बदबू आती है कहते हुए विधायक महोदय गुस्से में बनियान और टॉवेल में ही कैंटीन में घुस गए। उन्होंने कैंटीन के गरीब-दुर्बल कर्मचारियों पर बेरहमी से हमला किया। उन पर लात-घूंसों से हमला किया, गालियां दीं। पचास खोकों की टॉनिक पिए विधायक के शक्तिशाली मुक्कों के सामने उन गरीब लोगों की क्या चलती? इस हाथापाई में विधायक की कमर में बंधा ढीला तौलिया खुल जाने की आशंका थी और महाराष्ट्र को एक अनचाहा नजारा देखना पड़ता। विधायक गायकवाड जिस तरह से गरीब कर्मचारियों को बॉक्सर की तरह मुक्के

मार रहे थे उसे देखते हुए एक मुक्का जानलेवा हो सकता था इसलिए विधायक गायकवाड पर हत्या का प्रयास, सार्वजनिक स्थान पर मारपीट, अपमान, गाली-गलौज, धमकी जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए था। कैंटीन पर कार्रवाई होगी, लेकिन क्या गृह मंत्री को इस बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था कि सत्ताधारी दल का विधायक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र वाले परिसर में एक कर्मचारी की हत्या की कोशिश कर रहा है? लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि, यह मारपीट ठीक नहीं है। यह सभापति के अधिकार क्षेत्र का मामला है। उन्हें ही फैसला लेना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे। क्या मौजूदा सभापति या अध्यक्ष मुख्यमंत्री से पूछे बिना फैसला ले सकते हैं? विधायकों की अयोग्यता के मामले में दबाव में फैसले लेनेवालों और दिल्ली से आए फैसले के कागज पढ़नेवालों से मुख्यमंत्री फैसले की उम्मीद करते हैं। जो अध्यक्ष विधानसभा में विपक्ष के नेता के मामले में फैसला लेने को तैयार नहीं हैं और अनाप-शनाप जवाब देकर समय काट रहे हैं, वे हंगामा करनेवाले विधायकों पर कार्रवाई कैसे करेंगे? विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को नजराना देने के लिए इकट्ठा की गई करोड़ों की रकम धुले के एक विश्राम गृह में जब्त कर ली गई। विधानसभा अध्यक्ष को इस पर भी फैसला लेना है।

# आतंकवाद में डिजिटल तकनीकों का बढ़ता उपयोग चिन्ताजनक

-ललित गर्ग-

टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की नई रिपोर्ट में आतंकवादी गतिविधियों में डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट ने वैश्विक सुरक्षा के समक्ष एक नई और गहन चुनौती की ओर संकेत करते हुए आतंकवादी गतिविधियों में डिजिटल तकनीकों के बढ़ते प्रयोग को गहन चिन्ताजनक बताया है। रिपोर्ट में ई-कॉमर्स, ऑनलाइन भुगतान, सोशल मीडिया, क्रिप्टोकरेंसी और डार्कनेट जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण और संचालन के बढ़ते खतरे पर न केवल प्रकाश डाला गया है बल्कि गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट ने आतंकवाद के एक अलग ही पहलू की ओर ध्यान खींचा है। इसमें बताया गया है कि टेक्नॉलजी तक आतंकी संगठनों की आसान पहुंच उन्हें और खतरनाक बना रही है। इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर नई रणनीति एवं नियंत्रण नीति की जरूरत है। विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देशों में पलने-बढ़ने वाले आतंकी संगठन इन तकनीकों का उपयोग कर न केवल फंडिंग जुटा रहे हैं, बल्कि गोपनीयता और पहुँच के नए मार्ग भी तलाश रहे हैं। इसके अलावा, आतंकवादी संगठन अब विकेंद्रीकृत मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, जैसेकि अल-कायदा क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर धन जुटाना और संचालन करना। भारत ने समय-समय पर पाकिस्तान पोषित एवं पल्लवित आतंकवाद को बेनकाब करते हुए दुनिया से मिल रहे आर्थिक सहयोग पर चिन्ता जताई और कठोर कार्रवाई की मांग की, इस रिपोर्ट को भारत के रुख का समर्थन करने वाले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

एफएटीएफ के मुताबिक, 2019 में पुलवामा और 2022 में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुए आतंकी हमलों के लिए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। पुलवामा में आतंकियों ने आईईडी का इस्तेमाल किया था और इसे बनाने के लिए एल्युमिनियम पाउडर एमेजन से खरीदा गया था। गोरखपुर में हुए हमले में पैसों के लेनदेन में ऑनलाइन जरिया अपनाया गया। गोरखपुर वाले केस में आतंकी विचारधारा से प्रभावित शख्स ने इंटरनैशनल थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन और वीपीएन सर्विस का उपयोग किया था। इस

तरह से उसने आईएसआईएल के समर्थन में विदेश में धन भेजा था और उसे भी बाहर से आर्थिक मदद मिली थी। वीपीएन एक डिजिटल तकनीक है जो इंटरनेट उपयोगकर्ता की लोकेशन और पहचान को छुपाती है। जब कोई व्यक्ति वीपीएन का उपयोग करता है, तो उसका इंटरनेट ट्रैफिक एक एन्क्रिप्टेड सुरंग के माध्यम से किसी अन्य देश के सर्वर से होकर गुजरता है। इससे उसकी वास्तविक पहचान छिप जाती है और वह सेंसरशिप, ट्रैकिंग और जियो-रिस्ट्रिक्शन से बच सकता है।

2024 तक दुनिया में 150 करोड़ से अधिक वीपीएन यूजर्स हैं। इनमें से बड़ी संख्या एशिया और मध्य पूर्व से है, जहां सेंसरशिप या निगरानी से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में 12 से 14 करोड़ वीपीएन उपयोगकर्ता हैं। भारत वीपीएन यूजर्स की संख्या में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। वीपीएन का उपयोग कर आतंकी सोशल मीडिया और गुप्त चैनलों के जरिए युवाओं को बरगलाने और भर्ती करने का काम करते हैं। कुछ आतंकवादी समूह वीपीएन नेटवर्क का प्रयोग कर सरकारी वेबसाइटों, रक्षा प्रतिष्ठानों और बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमला करते हैं। दुनिया की एक तिहाई आबादी ऑनलाइन शॉपिंग करती है। इस साल ग्लोबल ई-कॉमर्स मार्केट के 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। भारत इस लिस्ट में फिलहाल सातवें नंबर पर है। लेकिन सवाल यह है कि इस डेटा के बीच अगर कुछ संदिग्ध लोग कुछ हजार डॉलर की खरीददारी करते हैं, जिसका इस्तेमाल आगे जाकर किसी आतंकी हमले में होता है, तो उसे चिह्नित कैसे किया जाए? एफएटीएफ ने कुछ दिनों पहले पहलगाम को लेकर कहा था कि इतना बड़ा आतंकी हमला बाहरी आर्थिक मदद के बिना संभव नहीं हो सकता। उसकी हालिया रिपोर्ट इसी बात को और पुष्ट कर देती है। आतंकियों ने अपने काम का तरीका बदल लिया है। वे इंटरनेट की दुनिया की ओट ले रहे हैं, जो ज्यादा खतरनाक है।

एफएटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी समूहों ने अब पारंपरिक धन स्रोतों के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल वित्तीय माध्यमों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये माध्यम उन्हें सरकार की नजरों से बचाते हुए सीमाओं के पार फंडिंग जुटाने की सहूलियत देते हैं। साथ ही, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर वे अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर भले हो गया हो, लेकिन उसके खिलाफ लगे आरोपों में कोई कमी नहीं आई है। अनेक ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और एफएटीएफ ऑब्जर्वेशन्स इस बात की पुष्टि करती हैं कि पाकिस्तान में आतंकी गुटों को डिजिटल इकोसिस्टम का खुले तौर पर उपयोग करने दिया जा रहा है, या कभी-कभी सरकार की मौन सहमति से। उदाहरण के रूप में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल टोकन के जरिए फंड जुटाने की नई तरकीबें अपनाई हैं। कई मामलों में आतंकी फंडिंग के लिए फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट और सामाजिक मीडिया अभियानों का सहारा लिया गया है। गजवा-ए-हिंद जैसे डिजिटल प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी जमीन से संचालित होकर भारत में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में लगे हैं।

भारत के विरुद्ध हाइब्रिड वारफेयर और साइबर जिहाद की रणनीति पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की नीति का हिस्सा बन चुकी है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दक्षिण एशिया में भारत सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां डिजिटल माध्यम से न केवल फंडिंग, बल्कि ब्रेनवॉशिंग और भर्ती का कार्य भी तेजी से हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को जाता है। उत्तर पूर्व में उग्रवादी संगठनों को डिजिटल भुगतान और चैनलों के माध्यम से सहायता मिलती रही है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान समेत उन सभी देशों से अपेक्षा की है कि वे डिजिटल वित्तीय निगरानी तंत्र को मजबूत करें। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। आतंकी संगठनों के ऑनलाइन अस्तित्व को समाप्त करने के लिए तकनीकी टूल्स विकसित करें। एफएटीएफ का चेतावनी के स्वरों में यह भी कहना है कि यदि आतंक के गढ़ एवं आतंकवाद को पोषित करने वाले इन देशों ने इन सिफारिशों पर अमल नहीं किया तो उन्हें हाई रिस्क जॉन की सूची में डाला जा सकता है। भारत को इस डिजिटल आतंकी खतरे से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से एक संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए-क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की रियल-टाइम निगरानी, साइबर आतंकवाद पर विशेष फोर्स का गठन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आतंकी कंटेंट की पहचान और हटाने के लिए मजबूत कानून, डार्क वेब और फेक डोनेशन चैनलों की सतत निगरानी आदि कदम उठाने चाहिए।

डिजिटल तकनीक ने जहां मानव जीवन को सरल और तेज किया है, वहीं इसका दुरुपयोग करके आतंकवाद को नया चेहरा देने की कोशिशें चिंता का विषय हैं। एफएटीएफ की चेतावनी को गंभीरता से लेने और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है। विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देशों पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना होगा ताकि वे अपनी धरती पर पनप रहे आतंकवाद एवं डिजिटल आतंकवाद के अड्डों को समाप्त करें। तभी एक सुरक्षित डिजिटल विश्व और शांतिपूर्ण वैश्विक समाज की कल्पना की जा सकती है। एफएटीएफ रिपोर्ट विश्लेषण करती है कि आतंकवादियों ने अपने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए वैश्विक दर्शकों से धन जुटाने के लिए सोशल मीडिया पर धन उगाहने वाले प्लेटफॉर्म और क्राउडफंडिंग माध्यमों से आतंकवाद के वित्तपोषण प्राप्त किया है। आतंकवादी संगठन पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल तरीकों से भी धन जुटाकर आतंकवाद को अंजाम दे रहे हैं। भारत ने एफएटीएफ रिपोर्ट को अपने रुख के समर्थन में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यह रिपोर्ट आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट आतंकवाद के वित्तपोषण और संचालन में शामिल देशों और व्यक्तियों पर दबाव बढ़ाने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायक हो सकती है।

# कौन है ये बुड़बक डूबे?

देश में जब से मोदी युग की शुरूआत हुई है, तब से भाजपा में कई हलके बकवास लोगों को इज्जत मिलने लगी है। पतिव्रता के गले में पत्थर की माला और वेश्या के गले में मणियों की माला कुछ ऐसी स्थिति सभी क्षेत्रों में बन गई है। निशिकांत दुबे के गले में भी ऐसी ही मणियों की माला है। यह सज्जन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र और मराठी लोगों के खिलाफ उन्होंने विष वमन किया है। यह दुबे सज्जन कहते हैं, अब महाराष्ट्र में क्या बचा है? महाराष्ट्र का वैभव खत्म हो गया है। महाराष्ट्र में कौन-सा बड़ा उद्योग है? तुम मराठी लोग हमारे धन पर जी रहे हो। यदि आप महाराष्ट्र से बाहर आओगे तो हम मराठी लोगों को पटक-पटककर मार डालेंगे। दुबे का यह बयान महाराष्ट्र का घोर अपमान है। दुबे मोदी-शाह के आशीर्वाद से ऐसे बयान देता है और क्योंकि उसे मोदी का अभय प्राप्त है इसलिए उसे अभय मिलता है। इस व्यक्ति ने यह कहकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ??की थी कि सुप्रीम कोर्ट देश में अराजकता पैदा करना चाहता है, लेकिन क्योंकि मोदी का अभय प्राप्त है इसलिए वह वहां भी बच निकला। दुबे की फर्जी एमबीए डिग्री का मामला चौंकानेवाला है। संसद के हलफनामे में उसने बताया कि वह एमबीए है। उसने शपथ लेकर कहा कि यह डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय की है, लेकिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही स्पष्ट कर दिया कि यह डिग्री बोगस है, जाली है तो इस आदमी को गिरफ्तार कर-के पूछताछ करनी चाहिए थी। संसद को धोखा देने के लिए इस दुबे की संसद की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन संसद को इतना बड़ा धोखा देने के बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दुबे का बचाव किया, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी की सारी डिग्रियां बोगस, जाली निकलीं। इसलिए यह पूरा मामला जैसा गुरु वैसा चेला वाला है। फिर, जब यह बोगस दुबे शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के खिलाफ विष वमन कर रहा था, तब मुख्यमंत्री फडणवीस और उनका नामर्द वैष्ठबिनेट दुम दबाए बैठा था।

अपनी आधी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए

दिल्लीश्वरों की गुलामी

अख्तियार करनेवाले फेकनाथ शिंदे और उसके चालीस चोर भी दुबे के महाराष्ट्र के प्रति अपमानजनक बयान के बाद से बिल में छिपे हुए हैं। भाजपा सरकार या महाराष्ट्र विधानसभा में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस दुबे को उसकी जगह दिखा सके, जो महाराष्ट्र का पानी दिखा सके। ऐसा लगता है जैसे यह कीड़ों का राज्य कीड़ों के लोगों के लिए चलाया जा रहा है। कोई लोफर निशिकांत दुबे दिल्ली में बैठकर मराठी लोगों का अपमान करता है और फडणवीस की वैष्ठबिनेट षंडों की तरह चुप रहती है। इसका राज यह है कि इस निशिकांत दुबे के असली आका मोदी और शाह हैं। इसके कारण आधी दाढ़ी पर हाथ फिरानेवालों की हालत पतली हो गई है। दुबे कहता है, महाराष्ट्र एक कंगाल राज्य है। पूरा देश जानता है कि इस देश में कंगाल या बीमार राज्य कौन हैं और कौन किसी की दया पर जी रहा है। महाराष्ट्र ने कभी अपनी रईसी का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र ने कड़ी मेहनत से जो धन और प्रगति अर्जित की है, उससे कई लोगों को ईर्ष्या है। कई लोगों ने महाराष्ट्र की संपत्ति को लूटने की कोशिश की है। यही कारण है कि मराठी लोगों को उनके उचित अधिकारों से वंचित किया गया है। जब कोई मराठी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ने निकलता है तो दूसरे प्रांतों के कौवे कांव-कांव करके मराठी व्यक्ति को प्रांतीयवादी ठहराने की कोशिश करते हैं। दूसरे सभी प्रांत अपनी भाषा, भूमि, अस्मिता के लिए लड़ते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जब मराठी अस्मिता की आवाज उठती है तो कंगाल राज्यों के बुड़बक डूबे शिवाजी महाराज के राज्य के खिलाफ जहर उगलते हैं। फिर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस जहर को बर्दाश्त करनेवाले और उस दुबे के खिलाफ विरोध का एक भी शब्द नहीं बोलनेवाले हुक्मरान महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठे हैं। आज महाराष्ट्र देश में जीएसटी के रूप में सबसे अधिक कर दे रहा है। अगर सभी हिंदी भाषी राज्यों को मिला दिया जाए तो भी जून २०२५ के लिए महाराष्ट्र का जीएसटी कर आंकड़ा (३०,५५३ करोड़ रुपए) इससे अधिक है। इससे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन किसकी दया पर जी रहा है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो की धमकी देने के लिए मुंबई को ही क्यों चुना? इन बुड़बकों को इसका गहन अध्ययन करना चाहिए।

**भाजपा के नए धर्मगुरु**

श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बैरिस्टर जिन्ना की जी हुजूरी कर रहे थे, तब महाराष्ट्र और मराठी लोग गुलामी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। मुंबई के मिल मजदूर करो या मरो के जोश के साथ सड़कों पर उतर आए थे। महाराष्ट्र दलाली के जाल और प्रलोभन में नहीं फंसा। यह सरस्वती और शौर्य का उपासक है। हिमालय की रक्षा का कर्तव्य सादि का ही है मानने वाला यह महाराष्ट्र कभी भी व्यापारिक दृष्टिकोण से काम नहीं करता। इसीलिए महाराष्ट्र का आचार-विचार आज भी मशाल की तरह धधक रहा है। महाराष्ट्र ने कभी किसी से द्वेष नहीं किया। जाति, धर्म और प्रांत की परवाह किए बिना भूखे लोगों को भोजन, पानी और आश्रय दिया। कोरोना काल में जब उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद कर दीं और अपने लोगों को बाहर रखा, तब महाराष्ट्र ही इन सभी हिंदीभाषियों का पालनहार था। जब हिंदीभाषियों के शवों को लावारिस मानकर प्रयागराज की गंगा में फेंका जा रहा था, तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही थे जिन्होंने महाराष्ट्र में इन सभी लोगों की ममतापूर्वक देखभाल की। ??तब यह डूबे कहां था? यह वही डूबे है, जिसने पहलगाम हमले में २६ महिलाओं के सिंदूर पोंछ दिए जाने के बाद कश्मीर जाकर पुलिस सुरक्षा में शराब पार्टी की थी। पहलगाम में भारतीय महिलाओं के सिंदूर की सुरक्षा के लिए एक भी पुलिसकर्मी नहीं था, लेकिन मोदी-शाह ने डूबे की भव्य शराब पार्टी की सुरक्षा के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मियों को लगा रखा था। यह मजाक है कि यह डूबे महाराष्ट्र को पटककर मारने की बात करता है। निशिकांत डूबे ने महाराष्ट्र को पटककर मारने की जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है।

मोदी-शाह ने महाराष्ट्र के खिलाफ अपना जहर उगलने के लिए इस डूबे के थोबड़े को चुना। डूबे का थोबड़ा यानी चौखटा एक गटर है। इस गटर से सुप्रीम कोर्ट और पहलगाम के निर्दोष पीड़ितों के बारे में लगातार गंदगी निकलती रहती है। इस गटर को एक बार वर्ली का गटर दिखाना ही होगा। अगर डूबे जैसे लोगों ने राज्यों और भाषाओं के बीच टकराव पैदा करने की सुपारी ली है और दलाली की है तो महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों को उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों को डूबे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना ही चाहिए।

# अमीरों का ही राज....गरीबों का कौन?

देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने रविवार को वही बात कही, जो मुख्य न्यायाधीश गवई ने चार दिन पहले कही थी। देश की संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में जमा है, जबकि बहुसंख्यक जनता दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, मुख्य न्यायाधीश ने इन शब्दों से आर्थिक प्रगति की पोल खोलकर रख दी थी। अब गडकरी ने भी सरकार के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। गडकरी ने कहा, देश में गरीबी बढ़ रही है, पैसा और संपत्ति चंद अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित हो रही है। नागपुर में सीए छात्रों के लिए एक सेमिनार में बोलते हुए गडकरी ने देश की प्रगति की असली तस्वीर सामने रखी। अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण हो रहा है और यह सही नहीं है, संपत्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, गडकरी ने भी अपनी राय रखी। सिर्फ इसलिए नहीं कि गडकरी ने ऐसा कहा, बल्कि देश में हो रही घटनाएं और हकीकत भी यही कहती हैं। देश की १४० करोड़ की आबादी में से १०० करोड़ से अधिक लोगों के पास सिर्फ अपनी कम से कम जरूरतों पर खर्च के लिए ही पैसे हैं। उनके पास दूसरे खर्चों के लिए पैसे नहीं बचते। सिर्फ १३-१४ करोड़ लोगों के पास ही

**न्यूनतम जरूरतों को पूरा करके**

अतिरिक्त खर्च करने की वित्तीय क्षमता है। देश के सबसे गरीब ५० फीसदी लोगों की आय २२.२ प्रतिशत से घटकर १५ प्रतिशत पर आ गई है। देश में मध्यम वर्ग की हालत भी अलग नहीं है। उनकी आय आधी हो गई है और बचत ५० साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है, वहीं अमीरों की संख्या भले ही बढ़ी नहीं है, लेकिन अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार इस तरह के कागजी घोड़े दौड़ाने में मशगूल है कि गरीबी कम हो रही है और पिछले बारह वर्षों में देश में गरीबों का प्रतिशत २७.१ प्रतिशत से घटकर ५.३ प्रतिशत हो गया है। यदि आपके अनुसार, देश का केवल ५ प्रतिशत हिस्सा ही गरीब है तो आपकी सरकार को ८५ प्रतिशत लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने की क्या जरूरत है?

मराठवाड़ा के वृद्ध किसान अंबादास पवार को बैल खरीदने के लिए पैसे न होने के कारण खुद को हल पर क्यों जोतना पड़ा? देश के आम किसानों को आज मौसम की मार और सरकार दोनों के हमलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? किसानों की आत्महत्या थमने को तैयार नहीं है। रविवार को बीड के एक युवा किसान राम फताले ने साहूकारों द्वारा परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र में पिछले सिर्फ तीन महीनों में ही ७६७ किसानों ने आत्महत्या

कर ली है। पूरे देश में पिछले १२ सालों में यही संख्या आठ हजार से ज्यादा है। साढ़े चार हजार से ज्यादा खेतिहर मजदूरों ने भी अपनी जान दे दी।

## फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले यूरोपीय देशों की संख्या बढ़ने पर एर्दोगन ने की सराहना

**एजेंसी**

**अंकारा।** तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने हाल के दिनों में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल द्वारा फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम यूरोपीय देशों की ओर से मानवीय भावना और न्याय की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण निर्णय है। एर्दोगन ने बताया कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से हाल ही में बातचीत की, जिन्होंने पिछले सप्ताह फ्रांस की ओर से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की थी। इसके बाद ब्रिटेन, कनाडा ( और पुर्तगाल ने भी इसी राह पर कदम बढ़ाया। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा, हमें यूरोप से खासकर फ्रांस और ब्रिटेन से आ रही मानवीय प्रतिक्रियाएं अत्यंत मूल्यवान लगती हैं। हम फिलिस्तीन को मान्यता देने की दिशा में उठाए गए हर कदम का स्वागत करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तुर्किये आने वाले दिनों में इजराइल पर और अधिक दबाव बनाएगा ताकि ग़ाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी गाजा में हो रहे अत्याचारों पर चुप नहीं रह सकता, जहां बच्चे भूख से मर रहे हैं और खाना ढूंढ रहे आम नागरिकों पर जानबूझकर गोली चलाई जा रही हैं। एर्दोगन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि वे इस गंभीर मानवीय संकट के समाधान के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करें और दो-राज्य समाधान की दिशा में ठोस पहल करे।

## ट्रंप ने मेक्सिको के साथ व्यापार समझौते की समयसीमा 90 दिनों के लिए बढ़ाई

**वॉशिंगटन।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि मेक्सिको के साथ व्यापार समझौते को लेकर तय 01 अगस्त की डेडलाइन को 90 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय ट्रंप और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत के बाद लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' पर पोस्ट में लिखा, 'मेक्सिको 25 फीसदी फेंटानिल टैरिफ, 25 फीसदी कारों पर टैरिफ और 50 फीसदी स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर पर टैरिफ देना जारी रखेगा। इसके अलावा, मेक्सिको ने अपने कई गैर-शुल्क व्यापार अवरोध को तुरंत समाप्त करने पर सहमति जताई है। उन्होंने आगे कहा कि अगले 90 दिनों में अमेरिका और मेक्सिको के बीच बातचीत जारी रहेगी, ताकि एक औपचारिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकें। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने भी एक्स पर पोस्ट में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। हमने कल घोषित टैरिफ वृद्धि को टाल दिया और बातचीत के जरिए दीर्घकालिक समझौता करने के लिए 90 दिन का समय हासिल कर लिया।

## कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 9 की मौत, 124 घायल

**कीव।** यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने रातभर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से भीषण हमला किया, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 124 अन्य घायल हो गए। मारे गए लोगों में 6 साल का एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 10 बच्चे घायल हुए हैं जिनमें सबसे छोटी 5 महीने की बच्ची है। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तिमुर त्काचेंको ने बताया कि एक नौ मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा हमले में ढह गया। स्थानीय निवासी याना जब्बोरोवा (35) ने बताया कि जब विस्फोट हुआ, तो घर की खिड़कियां और दरवाज़े उड़ गए। अब तो बस सदमा और तनाव ही बाकी है, क्योंकि और कुछ भी नहीं बचा है। यूक्रेनी वायु सेना के मुताबिक, रूस ने कुल 309 शहीद ड्रोन और 8 इस्कंदर-के क्रूज मिसाइलें दागीं। इनमें से 288 ड्रोन और 3 मिसाइलों को यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया, लेकिन 21 ड्रोन और 5 मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच गईं और भारी तबाही मचाई। हमले में कीव, द्नीप्रो, पोल्टावा, सुमी और मिकोलेव क्षेत्र निशाना बने, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव कीव पर पड़ा। राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा, आज दुनिया ने फिर देखा कि अमेरिका और यूरोप के साथ हमारी शांति की इच्छा का रूस ने कैसा उत्तर दिया। इसलिए शांति केवल ताकत के साथ ही संभव है।

## पाकिस्तान में पीटीआई के कई नेताओं को नौ मई के मामलों में 10 साल जेल की सजा

**इस्लामाबाद।** अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान की खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कई नेताओं को आज 2023 के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मामलों में सजा सुनाई गई। फैसलाबाद स्थित एक विशेष आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने इन नेताओं को 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब, सीनेट में विपक्ष के नेता शिबली फराज, जरताज गुल, एमएनए साहिबजादा हामिद रजा और पूर्व एमएनए शेख राशिद शफीक, पूर्व गृहमंत्री शेख रशीद अहमद के भतीजे उन 108 पीटीआई नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें इन दोषी ठहराया गया, जबकि 77 अन्य को बरी कर दिया गया। एटीसी ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल और हामिद रजा सहित लगभग 60 दोषियों को 10 साल और अन्य दोषियों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। एटीसी ने पीटीआई नेता फवाद चौधरी के साथ जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो, फैजुल्लाह कमोका, राणा असद महमूद खान, बिलाल अशरफ बसरा, हारून रशीद, अमारा रशीद, साहिबजादा हसन रजा और कामरान वराइच को बरी कर दिया गया।

# वाशिंगटन में दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री: मार्को रुबियो से की मुलाकात, ट्रेड डील को लेकर हुई बात

**एजेंसी**

**वाशिंगटन।** दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री चो ह्यून वाशिंगटन में अपने समकक्ष मार्को रुबियो से मुलाकात की। दोनों ने ट्रेड डील समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति जल्द ही एक शिखर सम्मेलन में शामिल होने अमेरिका आएंगे, उन तैयारियों का भी जायजा लेने ह्यून अमेरिका पहुंचे हैं। चो ह्यून और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि दो सप्ताह बाद वे व्हाइट हाउस में कोरियाई राष्ट्रपति ली से मुलाकात कर एक नए ट्रेड डील को आकार देंगे। योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, चो और रुबियो की इस मुलाकात में कई विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। इसमें उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे, द्विपक्षीय संबंधों को

बेहतर करने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर समन्वय को लेकर मंत्रणा की गई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बैठक की जानकारी दी और अमेरिका-कोरिया व्यापार समझौते पर भी टिप्पणी की।

पिगॉट ने कहा, ÷यह व्यापार समझौता, जो आज विदेश मंत्री रुबियो और कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून की बैठक के साथ हुआ है, अमेरिका-आरओके गठबंधन की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। यह गठबंधन पिछले 70 वर्षों से कोरियाई प्रायद्वीप और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि का आधार रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया को आरओके (रिपब्लिक ऑफ कोरिया) के नाम से संबोधित करता है। माना जा रहा है कि चो और रुबियो इस बैठक के दौरान ली-ट्रंप शिखर सम्मेलन के एजेंडा और समय निर्धारण पर भी बात कर सकते हैं।

इस बीच, कोरिया के उद्योग मंत्री किम जुंग-क्वान (जो व्यापार वार्ता प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं) ने बताया कि ट्रंप राष्ट्रपति ली से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं और उन्होंने विदेश मंत्री रुबियो को इस बैठक को शीघ्र तय करने का निर्देश दिया है।

## रूस में ऑनलाइन चरमपंथी सामग्री की तलाश भी पड़ेगी महंगी, विधेयक पर राष्ट्रपति पुतिन ने किए हस्ताक्षर

**एजेंसी**

**मास्को।** राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, जो ऑनलाइन चरमपंथी सामग्री तक पहुँचने या उसकी तलाश को अपराध घोषित करता है। इसके कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 5,000 रूबल (करीब 64 डॉलर) तक जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून 1 सितंबर से लागू होगा। रूस की संसद के दोनों सदनों ने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी, जिसके तहत इंटरनेट पर चरमपंथी घोषित सामग्री की तलाश अपराध माना जाएगा।दी मॉस्को टाइम्स के मुताबिक इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। यह कानून को रूस में इंटरनेट पर सरकारी नियंत्रण और सख्त करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर 'चरमपंथी' मानी जाने वाली सामग्री को तलाशता या एक्सेस करता है तो उस पर करीब 64 अमेरिकी डॉलर (लगभग 5000 रूबल) तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं किया गया है कि इसकी निगरानी किस तरह की जा सकेगी। किस तरह सर्च को ट्रैक किया जाएगा या किस आधार पर यह तय होगा कि किसने जानबूझकर ऑनलाइन ऐसी सामग्री खोजी है। रूस में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो वीपीएन का इस्तेमाल कर प्रतिबंधित साइट्स तक पहुंच बनाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ही वीपीएन सेवाओं के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाले एक और विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जो पिछले तीन वर्षों में रूस में व्यापक हो गए हैं। साल 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस में सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए ऑनलाइन सेंसरशिप और मीडिया बैन में इजाफा हुआ है।

## बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने लापता बुजुर्ग की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पाकिस्तान के विदेश, गृह मंत्रालय के सचिव को तलब किया

**एजेंसी**

**क्वेटा।** बलूचिस्तान उच्च न्यायालय ने बुजुर्ग नागरिक वाहिद कंबर बलूच के लापता होने के संबंध में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के सचिव को तलब किया। 19 जुलाई 2024 को ईरान से कथित तौर पर उनका अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के एक साल बाद भी उनका कोई अता-पता नहीं है। उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की सुनवाई करते हुए दोनों को अगली तारीख में पेश होने का आदेश दिया। द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वाहिद कंबर बलूच की ओर से अधिवक्ता हबीब ताहिर और शारी बलूच ने दायर की है। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पूर्व में पांच प्रतिवादियों को दिए गए नोटिसों की स्थिति के बारे में पूछताछ की। केवल दो जवाब प्रस्तुत किए गए, दोनों ही विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों की ओर से थे। एक जवाब में संकेत दिया गया कि मंत्रालय ने तेहरान स्थित पाकिस्तान के दूतावास से संपर्क किया। दूतावास ने बताया कि ईरान-इजराइल संघर्ष के कारण स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। फिर भी दूतावास ने कहा

कि जल्द से जल्द एक आधिकारिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। विदेश मंत्रालय के दूसरे जवाब में कहा गया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

वकील ने इस पर न्यायमूर्तिआमिर राणा से आग्रह किया कि वे संबंधित विभागों पर सख्त निर्देश जारी करें और उनकी बरामदगी सुनिश्चित करने और उनकी स्थिति के बारे में आधिकारिक बयान प्राप्त करने के लिए दबाव डालें। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति राणा ने कहा कि न्यायालय तदनुसार कार्यवाही करेगा हालांकि, उच्च न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र का मुद्दा भी उठाया और सवाल किया कि क्या वह विदेशी धरती पर हुए अपहरण से जुड़े मामले में फैसला सुना सकता है। जवाब में, वकील ने तर्क दिया कि वाहिद कंबर पाकिस्तान के नागरिक हैं और अपहरण चाहे कहीं भी हुआ हो, कार्रवाई करना राज्य के नाते पाकिस्तान और न्यायपालिका का कर्तव्य है, खासकर जब मौलिक संवैधानिक अधिकार दांव पर हों न्यायमूर्ति राणा ने वकील के तर्क से सहमत होते हुए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सचिव को अदालत में उपस्थित होने और अगली सुनवाई में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान वकील ने यह भी आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल के लापता होने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जिम्मेदार हो सकती हैं।

## राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पर संघीय सर्किट अपील न्यायालय में उठे सवाल, जजों ने आश्चर्य जताया

**एजेंसी**

**वाशिंगटन।** वाशिंगटन डीसी स्थित संघीय सर्किट अपील न्यायालय के न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के आपातकालीन शक्तियों के अभूतपूर्व उपयोग करते हुए अमेरिका के व्यापारिक साझेदार देशों पर व्यापक टैरिफ लगाने के अधिकार पर तीखे सवाल उठाए। कई न्यायाधीशों ने तो बार-बार इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि ट्रंप 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईपा) कानून का उपयोग करके टैरिफ को कैसे उचित ठहरा सकते हैं? अमेरिका ऑनलाइन अखबार पॉलिटिको की खबर के अनुसार, न्यायाधीश जिम्मी रेयना ने कहा, मेरी एक बड़ी चिंता यह है कि आईपी में टैरिफ शब्द का कहीं भी जिक्र तक नहीं है। न्यायाधीश टिमोथी डिक ने कहा, मेरे लिए यह समझना मुश्किल है कि कांग्रेस का इरादा आईपा में राष्ट्रपति को उस टैरिफ अनुसूची को रद्द करने का पूरा अधिकार देना था जिसे उसने वर्षों के गहन अध्ययन के बाद अपनाया था।अन्य न्यायाधीश इस तर्क पर सहमत दिखे कि ट्रंप ने एक ऐसे कानून का इस्तेमाल किया जिसका उद्देश्य राष्ट्रपतियों को किसी अंतरराष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियां प्रदान करना था, बल्कि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को हड़पना था। यहां यह महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश जिम्मी रेयना की नियुक्त ओबामा और न्यायाधीश टिमोथी डिक की नियुक्ति क्लिंटन ने की थी। खचाखच भरे न्यायालय में दो मुकदमों पर लगभग दो घंटे तक मौखिक बहस हुई। इन मुकदमों में ट्रंप के फरवरी और अप्रैल के बीच हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेशों में लगाए गए टैरिफ को चुनौती दी गई है। एक मामला निजी कंपनियों ने और दूसरा मामला 11 डेमोक्रेटिक नियंत्रित राज्यों ने दायर किया है। कुछ न्यायाधीशों ने मत व्यक्त किया कि अगर राष्ट्रपति बिना अदालतों की समीक्षा के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं (जैसा कि ट्रंप प्रशासन का दावा है और वह किसी भी आकार और अवधि के टैरिफ लगा सकते हैं) तो देश की जटिल और दीर्घकालिक व्यापार प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से अनावश्यक हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के एक पुरानी आपातकालीन शक्ति के तहत लगाए गए टैरिफ केवल इसलिए कानूनी चुनौतियों से बच पाए, क्योंकि वे एक समस्या पर केंद्रित थे और उनकी एक स्पष्ट समाप्ति तिथि थी। सुनवाई के दौरान 11 न्यायाधीशों ने राज्यों और निजी कंपनियों के वकीलों के तर्क सुने। ओबामा के कार्यकाल में नियुक्त न्यायाधीश रिचर्ड टारंटो ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वादी ने वास्तव में उन नकारात्मक परिणामों पर ध्यान दिया है, जिनका ट्रंप प्रशासन दावा करता है।

# गिलगित-बाल्टिस्तान में मूसलाधार बारिश से तबाही, 10 लोगों की मौत

**एजेंसी**

**इस्लामाबाद ।** पाकिस्तान-अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तेज बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लापता हैं। स्थानीय प्रशासन ने 37 बुरी तरह प्रभावित इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बाढ़ से पर्यटन और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक अनुमानित 20 अरब रुपए से अधिक की संपत्ति को नुकसान हुआ है।

जारी अधिसूचना के अनुसार, डायमर जिले के 12, गिलगित के 9, घिजर के 5, स्कर्दू और शिगर के 4-4, गांचे के 2 और नगर व खरमंग जिलों के 1-1 क्षेत्र को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। अधिसूचना में कहा गया, मॉनसून

2025 के दौरान हुई भारी बारिश के चलते गिलगित, घिजर, नगर, दीमर, स्कर्दू, गांचे, शिगर और खरमंग जिलों के कई मौजों में बाढ़ ने गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इनमें मानव जीवन, मवेशियों, घरों, बुनियादी ढांचे और खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय अधिकारी फैजुल्लाह फराज के अनुसार, अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। चार अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई है।

इस बीच, पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (पीएमडी) ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बाढ़ की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार, पंजाब, खैबर-पख्तूनख्वा, उत्तर-पूर्वी बलूचिस्तान, पाकिस्तान-अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, इस्लामाबाद में 40 प्रतिशत बारिश और तूफान की संभावना जताई गई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में बारिश ने जमकर तबाई मचाई है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को मौत हुई हैं और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है।

## हमास ने की स्थायी समाधान की अपील, कहा- युद्ध समाप्त करना 'मानवीय और नैतिक कर्तव्य'

**एजेंसी**

**न्यूयॉर्क/गाजा।** संयुक्त राष्ट्र में इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दे पर हुए हालिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बाद फिलिस्तीनी संगठन हमास ने एक बयान जारी कर कहा है कि गाजा में युद्ध का अंत करना एक मानवीय और नैतिक कर्तव्य है।हमास ने बयान में कहा कि हम अपने फिलिस्तीनी लोगों और उनके वैध अधिकारों के समर्थन में किए गए किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रयास की सराहना करते हैं और उसका स्वागत करते हैं।

हालांकि हमास ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक इजराइल गाजा पर अपना हमला बंद नहीं करता, तब तक किसी भी राजनीतिक समाधान की कोई संभावना नहीं है। उसने इजराइल पर नरसंहार और व्यवस्थित भुखमरी नीति अपनाने का आरोप लगाया।हमास ने संकेत दिया कि वह युद्ध को समाप्त करने और इजराइली बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए एक स्थायी संघर्षविराम समझौते की जरूरत है। जिसमें गाजा से इजराइली सेनाओं की पूर्ण वापसी, सीमा पारियों (क्रॉसिंग्स) को खोलना और पुनर्निर्माण कार्यों की तत्काल शुरुआत शामिल हो। हमास ने अपने बयान में दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हुए कहा कि ÷हमें एक ऐसे राजनीतिक रास्ते की ओर बढ़ना होगा जो कब्जे के अंत की ओर ले जाए और हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करे, जिसमें यरुशलम को राजधानी बनाकर एक पूर्ण संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना हो।

# अवामी एक्शन कमेटी नेता की 'ऑनर किलिंग', मानवाधिकार आयोग ने जताई कड़ी आपत्ति

**एजेंसी**

**इस्लामाबाद ।** पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान (पीओजीबी) के तंगिर जिले में अवामी एक्शन कमेटी के उपाध्यक्ष जावेद नाजी और एक विवाहित महिला की 'ऑनर किलिंग' के नाम पर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात की मानवाधिकार आयोग पाकिस्तान (एचआरसीपी) ने कड़ी निंदा की है और इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। एचआरसीपी ने अपने बयान में कहा, 'जावेद नाजी की हत्या उनकी मां और पत्नी की आंखों के सामने की गई, जो इस बर्बरता की पराकाष्ठा है। यह तंगिर जिले में एक हफ्ते के भीतर दूसरा ऐसा मामला है, जिसमें दो पुरुषों और दो महिलाओं को इज्जत के नाम पर मार दिया गया है। आयोग ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि

इस मामले की तत्काल, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और ऑनर किलिंग की संस्कृति को जड़ से खत्म किया जाए। एचआरसीपी की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में अब तक पाकिस्तान में 405 ऑनर किलिंग के मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में अधिकतर महिलाएं ही शिकार बनी हैं, जिन्हें अपने ही परिजनों की ओर से परिवार की इज्जत के नाम पर मारा गया। हाल ही में, बलूचिस्तान में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां एक स्थानीय कबायली पंचायत के आदेश पर एक जोड़े को मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। इस घटना के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए आसिफ ने पीड़ितों की बजाय बलूच समुदाय को ही दोषी ठहराया और कहा, जुल्म करने वाले तो आपके अपने ही भाई हैं। बलूच कार्यकर्ताओं ने मंत्री के बयान को शर्मनाक और अफसोसजनक बताते हुए कहा कि मंत्री सरकार की नाकामी और कानून व्यवस्था की लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।

## भारत समेत 60 देशों पर अमेरिकी टैरिफ सात अगस्त से होगा प्रभावी,ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए

**एजेंसी**

**वाशिंगटन।** राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने भारत समेत 60 से अधिक अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों के निर्यात पर नए टैरिफ (शुल्क) की घोषणा की। शुल्क की यह दर 07 अगस्त से प्रभावी होगी। इसमें भारत पर 25 फीसद और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने वैश्विक व्यापार को फिर से पटरी पर लाने की अपनी क्रांतिकारी योजना को आगे बढ़ाते हुए आधीरात से कुछ पहले इस आशय के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।द न्यूयॉर्क टाइम्स, सीबीएस न्यूज और एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, 60 से अधिक देशों पर टैरिफ 07 अगस्त की रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा। इसका अपवाद सिर्फ कनाडा है, जिसके निर्यात पर 01 अगस्त की रात 12:01 बजे से टैरिफ लागू होगा। कनाडा पर लगने वाले टैरिफ में उन सभी वस्तुओं को छूट दी गई है, जिनका व्यापार अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते के तहत होता है। इस समय कनाडा से अमेरिका के आयात का बड़ा हिस्सा इन्हीं वस्तुओं का है। कार्यकारी आदेश में कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिन्होंने प्रशासन के साथ व्यापार समझौते तोड़ दिए हैं और दर्जनों ऐसे देश हैं जिनके बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। सीरिया के लिए यह शुल्क 41 फीसद, लाओस, म्यांमार के लिए 40 फीसद तक हैं। कार्यकारी आदेश में साफ किया गया है कि किसी भी देश के आयात पर 10 प्रतिशत से कम टैरिफ नहीं लगेगा।सनद रहे ट्रंप ने पहले एक अगस्त की मध्यरात्रि के बाद से उच्च शुल्क लगाने की प्रतिज्ञा की थी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त सात दिनों की मोहलत देने का उद्देश्य सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा को नई टैरिफ दरों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय देना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 से अधिक देशों पर मुक्ति दिवस पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। बाद में उसे 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद उन्होंने व्यापार समझौतों के लिए आखिरी समय-सीमा अप्रैल में तय की। फिर 09 जुलाई की समय-सीमा आई और चली गई। व्हाइट हाउस ने फिर मोहलत दी। इसके बाद ट्रंप ने अधिकतर देशों के लिए आखिरी समय-सीमा पहली अगस्त तय की। गुरुवार की हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश की सूची में लगभग 70 व्यापारिक साझेदार शामिल हैं। जो देश सूची में नहीं हैं, उनके उत्पादों पर 10 फीसद टैरिफ लगेगा।

## ईरान की बढ़ती खुफिया गतिविधियों पर अमेरिका और नाटो सहयोगियों की कड़ी चेतावनी

**एजेंसी**

**वॉशिंगटन।** अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर ईरान पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बढ़ते खतरों के लिए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ईरान से स्पष्ट रूप से कहा है कि वह विरोधियों, पत्रकारों, यहूदी नागरिकों और पूर्व/वर्तमान अधिकारियों को निशाना बनाने की अपनी खुफिया गतिविधियां तुरंत बंद करे। जारी इस संयुक्त बयान में कहा गया कि हम ईरानी खुफिया एजेंसियों द्वारा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोगों की हत्या, अपहरण और उत्पीड़न के प्रयासों का एकजुट होकर विरोध करते हैं। यह हमारी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है।बयान में यह भी उल्लेख किया गया कि ईरानी खुफिया एजेंसियां अब अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि वे पत्रकारों, यहूदी नागरिकों और असहमति जताने वालों को निशाना बना सकें – जिसे पूर्णतः अस्वीकार्य बताया गया। बयान में चेतावनी दी गई है कि ऐसे किसी भी हमले को हमारी संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा, और हम सब मिलकर इन षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए काम करेंगे। किन देशों ने किया हस्ताक्षर इस संयुक्त बयान पर अमेरिका और नाटो के 13 सदस्य देशों अल्बानिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रिया, जो नाटो का सदस्य नहीं है।

# भारतीय हाई कमिश्नर ने साइप्रस के पर्यटन मंत्री से की मुलाकात, सीधी उड़ान को लेकर हुई बात

**एजेंसी**

**निकोसिया ।** भारत और साइप्रस के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इसी कड़ी में भारत के हाई कमिश्नर (उच्चायुक्त) मनीष ने निकोसिया में साइप्रस के उप पर्यटन मंत्री कोस्टास कूमिस से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पर्यटन सहयोग को और बढ़ाना था। बैठक में दोनों पक्षों ने विशेष पर्यटन पहलों के माध्यम से सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। साथ ही यह भी विचार किया गया कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवाएं शुरू करने के लिए एयरलाइंस को किस तरह से जोड़ा जा सकता है। इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि दोनों देशों के बीच संपर्क को और गहरा किया जाएगा। सांस्कृतिक आदान-प्रदान और ऐतिहासिक विरासत के माध्यम से रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में गंभीर चर्चा हुई। भारत के साइप्रस स्थित उच्चायोग ने अपने एक्स पोस्ट में जानकारी दी, उच्चायुक्त मनीष ने साइप्रस के उप पर्यटन मंत्री कोस्टास कूमिस से मुलाकात की और पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए विशेष पहलों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर भी बातचीत हुई। पोस्ट में आगे कहा गया, भारत और साइप्रस के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी के बीच, इस बैठक में द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक आदान-

प्रदान और फिल्म निर्माण में संभावित सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में दोनों देशों के बीच लोगों के स्तर पर रिश्तों को मजबूत करने, आपसी पहचान को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक संवाद के माध्यम से रिश्तों को गहरा करने की प्रतिबद्धता दिखाई दी। जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडूलाइड्स से विस्तृत बातचीत की थी। इस बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने पर्यटन बढ़ाने और भारत-साइप्रस के बीच सीधी हवाई सेवा की संभावनाओं पर भी बात की थी दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक और जन-जन के संपर्क को बढ़ावा देने को विशेष महत्व दिया। साथ ही 2025 के अंत तक मोबिलिटी पायलट प्रोग्राम अरेंजमेंट को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी।

## सर्राफा बाजार में सस्ता हुआ सोना, चांदी की भी घटी चमक

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** घरेलू सर्राफा बाजार में अगस्त के पहले दिन आज गिरावट का रुख नजर आ रहा है। सोना आज 420 रुपये से 470 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। इसी तरह चांदी के भाव में भी आज 2,200 रुपये प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है। कीमत में कमी आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,00,020 रुपये से लेकर 1,00,170 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 91,690 रुपये से लेकर 91,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोने की तरह चांदी के भाव में भी कमी आने के कारण आज ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,14,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,00,170 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 91,840 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,00,020 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 91,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,00,070 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,740 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

## अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का दूरसंचार निर्यात प्रतिस्पर्धी बना रहेगा: सिंधिया

**नई दिल्ली।** केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अतिरिक्त टैरिफ (शुल्क) लगाए जाने के बाद भी अमेरिका में भारतीय दूरसंचार उपकरणों का निर्यात प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। उन्होंने प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ के दूरसंचार उपकरणों के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर कहा, हम प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने भारत में पहली सेलुलर कॉल की 30वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली स्थित होटल ले मेरिडियन में कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट), ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (एआईएमआरए और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एसोसिएशन (ओरा) के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में डिजिटल क्रांति आ गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के चलते यूपीआई के जरिए 2.5 बिलियन लेन-देन प्रतिवर्ष हो रहे हैं। हम 4जी उपकरण खुद बनाने वाले 5वें देश बन गए हैं, अब 6जी में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से 6.5 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 17 बिलियन डॉलर का निवेश होगा।

## स्वास्थ्य सेवा और आवास नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी का एचडीएफसी कैपिटल से करार

**नई दिल्ली।** उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। डीपीआईआईटी ने यह समझौता किफायती आवास और प्रॉपटेक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए किया है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर औपचारिक रूप से डीपीआईआईटी के निदेशक मोहम्मद इशरार अली और एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ विपुल रूंगटा ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस साझेदारी का उद्देश्य आवासीय रियल एस्टेट विकास चक्र में दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए एचडीएफसी कैपिटल की पहल का हिस्सा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किफायती आवास विकास पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ाव, उभरती हुई प्रॉपटेक कंपनियों में रणनीतिक निवेश और त्वरक, शैक्षणिक संस्थानों और निवेशकों के सहयोग से मार्गदर्शन के माध्यम से विकास के अवसरों को सुगम बनाना है।

## डॉलर की तुलना में कमजोर हुआ रुपया, 16 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुई भारतीय मुद्रा

**नई दिल्ली।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और जुर्माना लगाने का ऐलान करने का असर आज भी भारत के मुद्रा बाजार में साफ-साफ नजर आया। मुद्रा बाजार में बने नकारात्मक माहौल और घरेलू शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण रुपया आज एक बार फिर डॉलर की तुलना में गिरावट का शिकार हो गया। आज डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा 16 पैसे फिसल कर 87.60 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन भारतीय मुद्रा 87.44 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत भी गिरावट के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 25 पैसे की कमजोरी के साथ 87.69 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के कुछ देर बाद ही बाजार में बने नकारात्मक माहौल के कारण रुपया 31 पैसे की गिरावट के साथ 87.75 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, दोपहर 12 बजे के बाद स्टॉक मार्केट की जोरदार रिकवरी के कारण विदेशी निवेशकों ने भी लिवाली शुरू कर दी।

# जबरदस्त उतार-चढ़ाव के बाद गिरा घरेलू शेयर बाजार, निवेशकों को लगी 2.59 लाख करोड़ की चपत

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** घरेलू शेयर बाजार आज जबरदस्त उतार-चढ़ाव का गवाह बना। आज के कारोबार की शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ हुई थी। दिन के पहले सत्र में लगातार दबाव बना रहा, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद खरीदारों ने आक्रामक अंदाज में लिवाली करके शेयर बाजार को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। सेंसेक्स निचले स्तर से 1,100 अंक से अधिक उछल गया। इसी तरह निफ्टी निचले स्तर से 320 अंक से अधिक की छलांग लगाने में सफल रहा। हालांकि मंथली एक्सपायरी की वजह से आखिरी 1 घंटे के कारोबार में बिकवाली का दबाव बन जाने के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक एक बार फिर लाल निशान में गिर गए। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.36 प्रतिशत और निफ्टी 0.35 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस और मेटल सेक्टर के शेयरों में जम कर बिकवाली होती रही। इसी तरह पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और टेक इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर, एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में आज खरीदारी होती रही। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार बिकवाली होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.85 प्रतिशत की कमजोरी के साथ आज के कारोबार का अंत किया।आज शेयर बाजार में आई कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 449.70 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 452.29 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 2.59 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो गया।आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,153 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,606 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,411 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 136 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,658 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 872 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,786 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 8 शेयर बढ़त के साथ और 22 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 13 शेयर हरे निशान में और 37 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 786.36 अंक की कमजोरी के साथ 80,695.50 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होने के बाद से ही खरीदारों ने लिवाली का जोर बनाने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे इस सूचकांक की चाल में सुधार होना शुरू हो गया। दोपहर 12 बजे के बाद खरीदारों ने लिवाली और तेज कर दी, जिसकी वजह से दोपहर 2 बजे के करीब सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से 1,108.12 अंक उछल कर 321.41 अंक की मजबूती के साथ 81,803.27 अंक तक पहुंच गया। हालांकि ये तेजी अधिक देर तक टिक नहीं सकी। इसके बाद मंथली एक्सपायरी की वजह से बाजार में बिकवाली शुरू हो गई।

## ईडी ने अनिल अंबानी को भेजा समन, 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया



**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी को 17 हजार करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनको 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अनिल अंबानी को भेजे गए समन में नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है, क्योंकि मामला यहीं दर्ज किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज किये जाएंगे।अनिल अंबानी को यह समन पिछले हफ्ते केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से उनके व्यावसायिक समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी के बाद जारी किया गया है। 24 जुलाई को शुरू हुई ईडी की यह छापेमारी तीन दिनों तक मुंबई में 35 से अधिक ठिकानों पर चली थी, जिनमें 50 कंपनियां और 25 लोग शामिल थे, इनमें अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के कई अधिकारी भी शामिल थे।

## मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सिंगापुर यात्रा सफल, 45,000 करोड़ के निवेश समझौतों पर हुए हस्ताक्षर : नारा लोकेश

**एजेंसी**

**अमरावती।** राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सिंगापुर यात्रा सफल रही और पांच वर्षों में 45,000 करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मंत्री ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि वे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें सीधे लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्सेलर मित्तल को जूम कॉल के ज़रिए निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। आर्सेलर मित्तल लक्ज़मबर्ग स्थित एक बहुराष्ट्रीय इस्पात निर्माण कंपनी है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है। लोकेश ने खुलासा किया कि देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट और डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। लोकेश का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 2019 से 2024 के बीच आंध्र प्रदेश ब्रांड को बर्बाद कर दिया। चंद्रबाबू की सरकार 2014 में राज्य के पुनर्गठन के बाद सिंगापुर ने



अमरावती के संयुक्त विकास के लिए हर कदम उठाए और राजधानी के निर्माण के लिए समझौता भी किया था लेकिन पिछली सरकार ने बिना सोचे समझे अलग नीति अपनाकर किसी के भी बात सुने बिना समझौते रद्द कर दिए।मंत्री लोकेश ने कहा कि पारदर्शिता के मामले में विश्व में सिंगापुर सबसे आगे है। ऐसे देश को जगन ने भ्रष्ट करार दिया था। जगन की सरकार ने अमरराजा बैटरीज और लुलु समेत कई कंपनियों को भगा दिया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू हैं जो नई राजधानी अमरावती के लिए पूरा जुड़ गए हैं। हमने वर्तमान में विशाखापत्तनम को आईटी के नक्शे पर लाने का फैसला किया है। इससे राज्य का विकास दस गुना होने की अपेक्षा है। लोकेश ने कहा कि हमने टीसीएस को 99 रुपये प्रति एकड़ की दर से ज़मीन आवंटित की, जो किसी भी राज्य ने नहीं दी। वाईएसआरसीपी के नेता इस मामले को लेकर अदालत गए। इससे राज्य के युवा को नौकरियां आएंगी। इसमें क्या ग़लत है? हमारी सरकार ने 14 महीनों में जो निवेश किया है, वह वाईएसआरसीपी द्वारा किए गए निवेश से ज़्यादा है।

## स्टॉक मार्केट में श्री रेफ्रिजरेशंस की जोरदार एंट्री, 40 प्रतिशत मुनाफे में आईपीओ निवेशक

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** एचवीएसी सिस्टम्स बनाने वाली कंपनी श्री रेफ्रिजरेशंस के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 125 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 35.88 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 169.85 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण सुबह 11 बजे तक कंपनी के शेयर उछल कर 175 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। इस तरह अभी तक के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को लगभग 40 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है। श्री रेफ्रिजरेशंस का 117.33 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 29 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 187.55 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन




167.32 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 197.01 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 195.05 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 94.52 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 18.25 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिए बेचे गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 2.57 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 11.53 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 13.55 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 39 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 99.01 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

## सेलोरैप इंडस्ट्रीज की स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री, लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी सेलोरैप इंडस्ट्रीज के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 83 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 8.43 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 90 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण इस शेयर की चाल में तेजी आ गई। लगातार हो रही लिवाली के कारण दोपहर 12 बजे के करीब सेलोरैप इंडस्ट्रीज के शेयर उछल कर 94.50 रुपये के अपर सर्किट लेवल तक पहुंच गए। इस तरह कंपनी के आईपीओ निवेशकों को पहले दिन ही 13.86 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है। सेलोरैप इंडस्ट्रीज का 30.28 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 29




जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 65.09 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 18.76 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 117.81 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। ये पूरा आईपीओ फ्रेश शेयरों का था। इसके तहत कुल 36.48 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। सेलोरैप इंडस्ट्रीज की ये लिस्टिंग ग्रे मार्केट की उम्मीदों से थोड़ी बेहतर रही। लिस्टिंग से पहले सेलोरैप इंडस्ट्रीज के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में करीब 6 प्रतिशत के ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे थे। ऐसे में आज ग्रे मार्केट प्रीमियम से ऊंचे स्तर पर हुई लिस्टिंग से आईपीओ निवेशकों को तुलनात्मक रूप से अधिक फायदा हुआ है। इस इश्यू का बुक रनिंग लीड मैनेजर ग्रेटेक्स कॉरपोरेट सर्विसेज था। वहीं पूर्वा शेयरेगिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था।

## मजबूत लिस्टिंग के बाद बिकवाली के दबाव में लुढ़के पटेल केम के शेयर

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** फार्मास्युटिकल एक्सीपीएंट्स और स्पेशियलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी पटेल केम स्पेशियलिटीज लिमिटेड के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। हालांकि, लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण निवेशकों की खुशी फीकी पड़ गई। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 84 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 31 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 110 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण इस शेयर की चाल में गिरावट आ गई। लगातार हो रही बिकवाली के कारण दोपहर 12 बजे के करीब पटेल केम स्पेशियलिटीज के शेयर फिसल कर 104.55 रुपये के स्तर तक पहुंच गए। इस गिरावट के बावजूद कंपनी के आईपीओ निवेशकों को अभी तक के कारोबार में 24.46 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है। पटेल केम स्पेशियलिटीज लिमिटेड का 59 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 29 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 167 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये पूरा आईपीओ फ्रेश शेयरों का था। इसके तहत कुल 70 लाख शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। पटेल केम स्पेशियलिटीज लिमिटेड की ये लिस्टिंग ग्रे मार्केट की उम्मीदों के मुताबिक ही रही। ग्रे मार्केट के आंकड़ों के अनुसार लिस्टिंग से पहले कंपनी के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में करीब 111 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे।

# छत्तीसगढ़ को मिली 600 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात

**एजेंसी**

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना को रफ्तार देने के लिए आज एक अहम क़दम उठाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाक़ात की, जिसमें राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंज़ूरी मिली। बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 600 करोड़ रुपये की मंज़ूरी। इसके ज़रिए छत्तीसगढ़ में कई सड़कों के निर्माण और उन्नयन का रास्ता साफ़ हुआ है। इसके साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाले दो लेन मार्ग को चार लेन में अपग्रेड करने की योजना को भी मंज़ूरी मिली है।रायपुर शहर की भीड़भाड़ को कम करने के लिए चार बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे, जिनका भूमि पूजन शीघ्र ही होगा। वहीं, राजधानी रायपुर से अन्य ज़िलों तक की सड़कें दो लेन से चार लेन में बदली जाएंगी, जिससे आवागमन तेज़ और सुरक्षित हो जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि राज्य की सभी सड़क योजनाएं अब केंद्र के 'गति शक्ति पोर्टल' के ज़रिए भेजी जाएंगी, ताकि जल्द मंज़ूरी मिल सके। श्री गडकरी ने रायपुर (आरंग)-बिलासपुर (दर्री) के बीच करीब 95 किमी लंबी छह लेन सड़क के लिए डीपीआर भेजने को कहा, जो औद्योगिक, कृषि और शैक्षिक क्षेत्रों को जोड़ेगी। साथ ही, नागपुर से रायपुर तक प्रस्तावित 300 किमी लंबा समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भी शीघ्र डीपीआर मांगा गया है।इसके अलावा कुछ ज़रूरी योजनाओं को आज मंज़ूरी भी मिल गई। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 ए में उन्नयन कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में रेजिंग का कार्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में मजबूतीकरण के कुल 115.95 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति मिली है। इनमें बिलासपुर शहर के भीतर 15 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शामिल है, जिससे शहर में ट्रैफिक आसान होगा। कटनी-गुमला मार्ग के हिस्से में 11 किलोमीटर सड़क बनेगी जो गांवों को जोड़ने में मदद करेगी। वहीं, केशकाल के 4 किलोमीटर हिस्से की सड़क को मज़बूत किया जाएगा, जिससे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 7000 करोड़ रुपये से ऊपर के नियोजित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति को भी शीघ्र करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़कें केवल यात्रा का साधन नहीं हैं बल्कि विकास, रोज़गार और सामाजिक बदलाव का रास्ता हैं। अंजोर विजन 2047' के तहत छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव, हर नागरिक तक बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन पहुंचे। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित थे।

## शांति गोल्ड की स्टॉक मार्केट में प्रीमियम लिस्टिंग, फायदे में आईपीओ निवेशक

**एजेंसी**

**नई दिल्ली।** रत्नाभूषण का काम करने वाली कंपनी शांति गोल्ड के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूत एंट्री की। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 199 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 229.10 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 227.55 रुपये के स्तर पर हुई। इस तरह आईपीओ निवेशकों को शुरू में ही करीब 15 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन मिल गया। लिस्टिंग के बाद लिवाली शुरू हो जाने के कारण सुबह 11 बजे तक कंपनी के शेयर उछल कर 230.25 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। इस तरह अभी तक के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को लगभग 15.70 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है। शांति गोल्ड का 300.13 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 29 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 80.78 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 117.33 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 151.17 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 29.73 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 1,80,96,000 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने जयपुर में प्रस्तावित फैसिलिटी का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने. वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 19.82 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 26.87 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 65.84 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 27 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 1,112.47 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

## एनएसडीएल का आईपीओ 760-800 रुपये प्राइस बैंड के साथ खुला, एक अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

**एजेंसी**

**जयपुर।** नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) का बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 30 जुलाई को निवेशकों के लिए खुल गया है और यह 1 अगस्त को बंद होगा। यह निर्गम पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के रूप में जारी किया गया है, जिसमें कंपनी की ओर से कोई नया शेयर जारी नहीं किया जा रहा है। इस आईपीओ के अंतर्गत कुल 50,145,001 इक्विटी शेयरों की बिक्री की जा रही है। यह बिक्री आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम जैसे मौजूदा शेयरधारकों द्वारा की जा रही है। कंपनी ने 2 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों के लिए 760 से 800 रुपये प्रति शेयर का मूल्य बैंड तय किया है। निवेशक न्यूनतम 18 शेयरों और उसके बाद 18 के गुणकों में आवेदन कर सकते हैं। एंकर निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया 29 जुलाई को पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य निवेशक 1 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के अंतर्गत सभी आवेदन अनिवार्य रूप से एएसबीए (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट) प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएंगे।

# टेक्सटाइल उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए होंगे हरसंभव प्रयास: मुख्यमंत्री डॉ यादव

**एजेंसी**

**भोपाल।** मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक और गुणवत्तापूर्ण कपास उत्पादन करने वाला राज्य है। राज्य सरकार ने कपास से धागा, कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। न केवल देश बल्कि अन्य देशों की टेक्सटाइल इकाइयों से भी अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बायर-सेलर के साथ चर्चा को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट में उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे। समिट में देश-दुनिया के कई इंडस्ट्री लीडर्स उपस्थित हुए। समिट में राज्य सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों के साथ निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर वन-टू-वन मीटिंग भी की। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश में निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश उद्योग प्रोत्साहक राज्य की छवि बनाते हुए सभी सेक्टर्स के उद्यमियों को आमंत्रित कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स का स्वागत करते हुए कहा कि देश ऐसे ही नहीं बदलता है, इसके लिए दृढ़ संकल्पों की आवश्यकता होती है। इन संकल्पों में नवीनता होती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी प्रकार के व्यवसायों को आगे बढ़ा रही है। औद्योगीकरण को गति प्रदान करने में बायर-सेलर वर्ग का विशेष स्थान होता है। प्रधानमंत्री मोदी के देश की बागडोर संभालने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

**ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत 42 कानूनों को किया खत्म**

उन्होंने कहा कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग के अंतर्गत 42 कानूनों को खत्म किया है, जो व्यापार में बाधा बनते थे। राज्य सरकार ने उद्योग शुरू करने के लिए जरूरी 29 अनुमतियों को भी कम करके 10 तक सीमित कर दिया है। प्रदेश में उद्योगपतियों को बिजली, पानी, जमीन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रमिकों के वेतन के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। मेक इन इंडिया से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमें प्रतिकूलता से आगे बढ़कर अनुकूलता की ओर बढ़ने की जरूरत है। राज्य सरकार ने डेढ़ साल के कार्यकाल में औद्योगीकरण का वातावरण तैयार किया है। सरकार खनन, पर्यटन, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है।

**टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं**

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल और गारमेंट्स सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं है। मध्य प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के आर्टिजंस और छोटे-छोटे उद्योग उपलब्ध है। राज्य की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों ने देश में ही नहीं, विदेश में भी अपनी पहचान बनाई है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। राज्य में निवेशकों को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वित्तीय प्रोत्साहन निवेशकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने की सुविधा है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में निवेश करने पर सरकार सभी नीतियों का पूर्ण लाभ प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4000 से अधिक दिनों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है। हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के लक्ष्य को मिलकर पूरा कर सकते हैं। राज्य सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

# उर्वशी रौतेला

## के 70 लाख के गहने चोरी, लंदन एयरपोर्ट से गायब हुआ बैग, भड़क गईं एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला किसी न किसी वजह के चलते सुर्खियों में छाई रहती हैं. अब उर्वशी ने दावा किया है कि हाल ही में उनका लंदन के गैटविक एयरपोर्ट से 70 लाख के गहनों से भरा लग्ज़री सूटकेस चोरी हो गया. एक्ट्रेस का ये भी कहना है कि वह विंबलडन के लिए शहर में थीं, जब उनका बैग लगेज बेल्ट से गायब हो गया. उर्वशी ने अपना बैग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला.उर्वशी की तरफ से उनकी टीम ने एक बयान जारी करते हुए कहा, एक प्लैटिनम एमिरेट्स सदस्य और विंबलडन में भाग लेने वाली एक ग्लोबल आर्टिस्ट के रूप में, मुझे यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि मुंबई से एमिरेट्स की हमारी उड़ान के बाद, लंदन गैटविक एयरपोर्ट पर बैगेज बेल्ट से हमारा क्रिश्चियन डायर ब्राउन बैगेज चोरी हो गया.

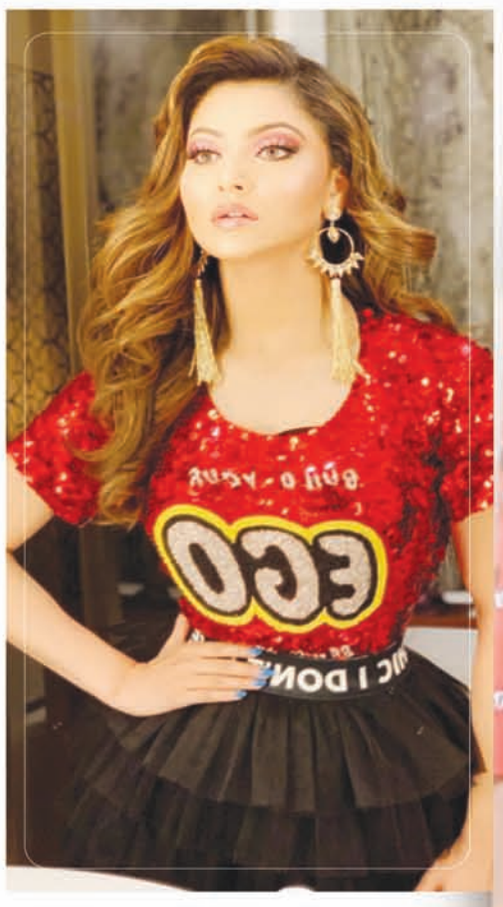

**लंदन एयरपोर्ट से 70 लाख के गहनों का बैग चोरी**

इतना ही नहीं बयान में आहे लिखा था, हमारे बैगेज टैग और टिकट होने के बावजूद, बैग बेल्ट एरिया से सीधे गायब हो गया. एयरपोर्ट की सुरक्षा का एक खतरनाक उल्लंघन. यह मामला केवल खोए हुए बैग का नहीं हैज्यह सभी यात्रियों की जवाबदेही, सुरक्षा और सम्मान का भी है. ब्यूटी पेजेंट में अपने मजबूत बैकग्राउंड के अलावा, उर्वशी कई बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रही हैं, जिनमें 'सिंह साहब द ग्रेट', 'सनम रे', 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' और 'हेट स्टोरी 4' का शामिल है.

उर्वशी ने 'लव डोज' और 'बिजली की तार' जैसे म्यूजिक वीडियो में भी अपने ग्लैमर का तड़का लगाया है. उर्वशी सोशल मीडिय पर काफी एक्टिव रहती हैं. बता दें, इस महीने की शुरुआत में, उर्वशी रौतेला की मां ने उनकी पूर्व मैनेजर वेदिका प्रकाश शेट्टी पर भी चोरी का आरोप लगाया था. मीरा रौतेला ने दावा किया कि वेदिका 2015 से 2017 तक उर्वशी के साथ भी जुड़ी रहीं और इस दौरान चोरी और धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल रहीं.

**उर्वशी रौतेला की मां ने किया था दावा**

उर्वशी की मा ने दावा किया, वेदिका प्रकाश शेट्टी ने 2015-2017 के दौरान मेरी बेटी के लिए 24/7 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में काम किया. लास वेगास में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता से लौटने के बाद और उसके बाद 2016 में मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज सौंपे जाने के दौरान उर्वशी की असिस्टेंट के लिए उन्हें रखा गया था. इस दौरान, उन्हें उर्वशी के कपड़ों, भारी गाउन और निजी सामान से लेकर कई ज़िम्मेदारियां सौंपी गईं थीं. हालांकि, जल्द ही हमें पता चला कि उन्होंने चोरी और धोखाधड़ी के कई काम किए थे.

## सबको हंसाने वाली अंगूरी भाभी ने रियल लाइफ में सहा दर्द ही दर्द, बताई शादी तोड़ने की वजह

टीवी का फेमस कॉमेडी सीरियल भाभी जी घर पर हैं 10 सालों से लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बना हुआ है. इसमें चार किरदार लीड में नजर आते हैं, जिनमें अनीता मिश्रा (विदिशा श्रीवास्तव), विभूति नारायण मिश्रा (आसिफ शेख), मनमोहन तिवारी (रोहितांश गौर) और अंगूरी तिवारी (शुभांगी अत्रे) जैसे बेहतरीन कलाकार हैं. शो में अंगूरी भाभी का रोल काफी मजेदार है, जिसे शुभांगी अत्रे बखूबी निभाती हैं. सबको हंसाने वाली शुभांगी रियल लाइफ में काफी दर्द से गुजरी हैं, खासकर उनकी शादी के बाद उन्होंने बहुत कुछ सहा है.सिद्धार्थ कन्नन को कुछ ही दिन पहले शुभांगी अत्रे ने एक इंटरव्यू दिया. शुभांगी ने इस दौरान 'भाभी जी घर पर हैं' में उन्हें अंगूरी का रोल कैसे मिला से लेकर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या-क्या सहा है, ये सबकुछ बताया है. इसी दौरान शुभांगी ने बताया कि शादी के बाद उन्हें अपने पति के बारे में कुछ चीजें पता चलीं जो उन्हें बहुत हर्ट कर गईं और फिर वो उनसे अलग हो गईं.

**शुभांगी अत्रे ने अपनी शादी क्यों तोड़ी थी ?**

इंटरव्यू में शुभांगी अत्रे से पूछा गया, 'आपको पता नहीं था कि आपके हसबैंड को शराब की लत थी ?' इसपर शुभांगी ने जवाब दिया, 'नहीं, मुझे इतना नहीं पता था. शादी के पहले तो बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन बाद में ये पता चला कि कभी कभी वो ड्रिंक करते हैं. मैं ज्यादा घर पर रहती नहीं थी, शूट के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाना ही पड़ता था. ईमानदारी से कहूं तो सच में मुझे नहीं पता था, मैं लंबे-लंबे समय के लिए शूट पर ही रहती थी तो घर पर रहना ज्यादा होता नहीं था. महादेव की कृपा थी कि मुझे काम की कमी रही नहीं और मैं लगातार काम करती रही.'

'मेरी बेटी आशी मुझे कभी-कभी बताती थी कि पापा ड्रिंक करते हैं, घर पर ही करते हैं और उनका बिहेव बहुत गलत होता है. वहां से मुझे बुरा लगने लगा, हमारा झगड़ा होता था. पूरी तरह से चीजें कोविड के समय पता चलीं, वो बहुत ड्रिंक करते थे और जब करते थे तब उनका बिहेव मुझसे और मेरी बेटी से खराब रहता था.

मेरा दिमाग हमेशा इसमें रहता था कि मुंबई है अपना घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए तो मैं उसपर काम करती थी. लेकिन कोविड के बाद हालात बहुत बिगड़े और मुझे अलग होने का फैसला लेना पड़ा था.'

## अजय देवगन की बेटी नीसा का क्या है करियर प्लान, कहां से की है पढ़ाई?

एक्टर अजय देवगन को फिल्म इंडस्ट्री में आए 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं. 1991 में फिल्म फूल और कांटे से अजय देवगन ने बॉलीवुड डेब्यू किया था और इन सालों में उन्होंने ढेरों फिल्में की हैं. 1999 में अजय देवगन ने एक्ट्रेस काजोल से शादी कर ली थी और 2003 में अजय-काजोल की पहली संतान नीसा देवगन हुई. नीसा अब 22 साल की हो गई हैं और अक्सर उन्हें पैपराजी कैमरों में कैद कर लेते हैं. सोशल मीडिया पर भी नीसा की तस्वीरें जमकर वायरल होती हैं, लेकिन फैंस जानना चाहते हैं कि नीसा किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं और उनका करियर प्लान क्या है ?नीसा ने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और उसके बाद से ही वो लाइमलाइट में ज्यादा रहने लगी हैं. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीसा देवगन जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करेंगी, लेकिन इसपर काजोल या अजय देवगन कुछ नहीं कहते हैं. उनका कहना है कि उनके बच्चे जो करना चाहें उन्हें पूरी छूट है. असल में नीसा देवगन का करियर प्लान क्या है ? आइए बताते हैं.

**नीसा देवगन किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं ?**

ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बच्चे धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करते हैं. नीसा की शुरुआती पढ़ाई उसी स्कूल से हुई. नीसा ने इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी और लग्जरी ब्रांड स्ट्रैटेजी में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है और उसकी डिग्री ली है. नीसा की ये पढ़ाई स्विट्जरलैंड के ग्लियन इंस्टिट्यूट से हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, काजोल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नीसा मूवी बिजनेस में कदम नहीं रखेंगी. अब आगे उनका क्या प्लान है वो ही जानती हैं.

**काजोल ने शेयर किया था नीसा के लिए खास वीडियो**

इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो शेयर करते हुए काजोल ने कैप्शन में लिखा था, 'सच में खास मौका हैज्तुम पर गर्व है. पूरी तरह से इमोशनल हूं.' इसके हैशटैग में काजोल ने ग्रेजुएशन, फर्स्ट बेबी और शी एन एडल्ट लिखा. इस वीडियो में नीसा के ग्रेजुएशन की तस्वीरों की झलक देखने को मिली.इसके कमेंट बॉक्स में रॉनित रॉय, ट्विंकल खन्ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वत्सल सेठ, विंदू दारा सिंह और सबा अली खान ने बधाई हो लिखा. इसके साथ ही काजोल के फैंस भी उनकी बेटी के ग्रैजुएट होने पर उन्हें बधाई दी है. वीडियो में जो तस्वीर है उसमें नीसा ने साड़ी पहनी है और उनके साथ उनके पापा अजय देवगन, मां काजोल और भाई युग देवगन नजर आ रहे हैं.

## मुझे मजबूरी में लीगल... प्रेमानंद महाराज को लेकर फैलाए जा रहे झूठ पर बोलीं

# दिशा पाटनी

### की बहन

एक्ट्रेस दिशा पाटनी भले ही इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा का वक्त बिता चुकी हैं लेकिन इसके बाद भी वे ज्यादा मुखर रहना पसंद नहीं करती हैं. उनकी तुलना में उनकी बहन खुशबू पाटनी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखती हैं. खुशबू ने हाल ही में अनिरुद्धाचार्य जी के बयान का विरोध किया था जो चर्चा में रहा था. इसके बाद उनपर इस बात का भी आरोप लगा कि वे प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ भी बयान दिया है. अब इसपर एक्ट्रेस ने स्टेटमेंट जारी किया है और अपनी सफाई दी है. साथ ही उन्होंने ट्रोल्स को भी करारा जवाब दिया है.

**खुशबू पाटनी ने स्टेटमेंट में क्या कहा ?**

खुशबू पाटनी ने ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा- ऐसा सुनने में आया है कि कुछ लोग मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने स्पिरिचुअल लीडर प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बुरा-भला बोला है. मैं इस बारे में पहले एकदम क्लियर कर देना चाहती हूं कि मैंने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं बोला है. मैंने जो कहा था वो पूरी तरह से अनुरुद्ध आचार्य द्वारा किए गए नारी द्वेष से जुड़े बयान पर केंद्रित था. मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि कुछ लोग मेरा और मेरे परिवार का नाम उन चीजों में डाल रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है. जैसी मिसइनफॉर्मेशन फैली हुई है वो सिर्फ अनइथिकल ही नहीं है बल्कि खतरनाक भी है.

**खुशबू पाटनी की धमकी**

आगे खुशबू पाटनी ने कहा- संत-महात्माओं की इज्जत में हमेशा से दिल से करती आई हूं. लेकिन अगर महिलाओं के विरोध में कुछ भी कहा जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो लोग झूठ फैला रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि सच हमेशा जीतता है. मैं दर्खास्त करती हूं कि जो लोग भी मिसलीडिंग वीडियोज और कंटेंट फैला रहे हैं वे ऐसा ना करें वर्ना मजबूरी में मुझे लीगल एक्शन लेना होगा.

**कौन हैं खुशबू पाटनी ?**

खुशबू पाटनी की बात करें तो वे बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बड़ी बहन हैं. दोनों की उम्र में करीब 6 महीने का फासला है. खुशबू पेशे से आर्मी अफसर रही हैं लेकिन अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है. एक्ट्रेस अब फिटनेस कोच और ऑन्त्रेप्रेन्योर हैं. हालांकि उनकी पब्लिक अपीयरेंस तो उतनी नहीं रहती हैं मगर सोशल मीडिया पर उनके स्टेटमेंट्स वायरल रहते हैं. उनकी बहन दिशा पाटनी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी हैं और वे भी अपनी फिटनेस की वजह से चर्चा में रहती हैं.

# बैराज बांध विस्थापित परिवारों ने 123वें दिन भी चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन व धरना दिया

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

**शाहपुर** कंडी में डैमज प्रशासन के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर बैराज बांध विस्थापित हुए परिवारों ने अपने रोजगार व अन्य मुआवजों की मांग को लेकर 123वें दिन भी अपनी भूख हडताल व रोष प्रदर्शन जारी रखा। आज 123वें दिन पर अमित शर्मा शाहपुर कंडी, अवधेश शर्मा शाहपुर कंडी, लेख राज डूंग, राकेश कुमार शाहपुर कंडी व अमित कुमार अदियाल ने अपनी भूख हडताल जारी रखी। विस्थापित परिवारों व कमेटी के पदाधिकारियों ने जिनमें कर्मचारी नेता जसवंत संधू व अन्य ने बताया कि , बैराज बांध के निर्माण के लिए बैराज बांध प्रशासन ने उनके प्रभावित हुए परिवारों की भूमि, आवास व अन्य बने हुए स्थानों को अधिगृहित कर लिया है,परंतु बनती आर एंड आर पालिसी अनुसार, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसकारण वह विवश हो कर रोष प्रदर्शन व भूख हडताल कर रहे है। रोष प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि पुरानी आर एंड आर पालिसी को बहाल किया जाए , उनका बनता रोजगार दिया जाए व पुनार्वास मुआवजा दिया जाए । इसके साथ ही विस्थापित परिवारों ने चेतावनी दी है कि यदि शीध्र ही उनकी उचित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह 18 अगस्त को बांध कार्यालयों के बाहर फिर से विशाल रोष प्रदर्शन व धरना देगें। इस अवसर पर कमेटी के पदाधिकारी , कर्मचारी नेता जसवंत संधू, रोहित कुमार, सुरजीत सिंह, रविंद्र बाबा, कुलदीप शर्मा, धर्मपाल , रमेश कुमार विनोद शर्मा, हरनाम सिंह, अंशू शर्मा, सुनीता देवी, बीतू देवी, विनोद कुमारी, आदर्श वाला व अन्य उपस्थित थे। डल्ली ं३ँ३ॅल्ल३

## मलेंद्र राजन ने मल्टीपर्पज आउटलेट का किया उद्घाटन, महिला समूहों को मिलेगा नया बाजार

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

विकास खंड कार्यालय परिसर में आज विधायक मलेंद्र राजन ने एक मल्टीपर्पज आउटलेट का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे जैविक और हस्तनिर्मित उत्पादों को अब एक सशक्त विपणन मंच मिलेगा। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों की ब्रांडिंग, गुणवत्ता और आकर्षक पैकेजिंग के लिए समूहों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा के अनुरूप मांग बढ़ाई जा सके। विधायक ने जानकारी दी कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से 'हिम ईरा शॉप्स' खोली जा रही हैं, और स्वयं सहायता समूहों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।

उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से इस मॉडल को और प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में एसडीएम डॉ. सुरिंद्र ठाकुर, बीडीओ सुदर्शन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कर्ण सिंह पठानिया, इंदौरा पंचायत प्रधान भूपाल कटोच, पूर्व उपप्रधान मनोहर सिंह, कांग्रेस कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा, अनिल कटोच, उमा कांत सूदन, धर्मेंद्र निक्का सहित अन्य गणमान्य एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

## न्यूज फ्लैश

### भोरंज में विकास कार्य ठप, जिला परिषद सदस्य राजकुमारी ने अपने ही पार्टी विधायक पर लगाए आरोप



दिव्य दिल्ली : हमीरपुर

भोरंज विधानसभा क्षेत्र के जाहू वार्ड से जिला परिषद सदस्य राजकुमारी ने अपने ही पार्टी के विधायक पर विकास कार्यों में अड़ंगा डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जाहू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में राजकुमारी ने कहा कि तथाकथित ह्लएक्सीडेंटल विधायकह्व ने दर्जनों सार्वजनिक कार्यों को जानबूझकर रोके रखा है और जिला परिषद के फंड का उपयोग तक नहीं होने दिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी कार्यकताओं की कोई इज्जत नहीं की जा रही। राजकुमारी ने कहा कि क्षेत्र में छह हैंडपंप आज तक नहीं लगाए गए हैं, जबकि एक्सईएन, जेई और एसडीओ को बार-बार अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वषार्शालिका और चैनलाइजेशन जैसे कार्यों पर विधायक अपने नाम के बोर्ड लगवा रहे हैं, जबकि असल में यह जिला परिषद की परियोजनाएं हैं। राजकुमारी ने सवाल उठाया कि एक साल में क्षेत्र में तीन पेट्रोल पंप तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 500 मीटर चैनलाइजेशन का काम अब तक नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि नाबार्ड से स्वीकृत 7.42 करोड़ रुपये की राशि के लिए डीपीआर बन चुकी है, परंतु काम आज तक शुरू नहीं हुआ। ठेकेदारों का कहना है कि विधायक की मंजूरी के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। राजकुमारी ने पूछा कि विधायक जनता के कामों को रोककर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने चेताया कि यदि यह रवैया जारी रहा तो जनता इसका उचित जवाब देगी।

### नशा तस्करी मामले में दोषी को तीन साल का कठोर कारावास, 10,000 जुर्माना

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

जिला पुलिस नूरपुर के अंतर्गत थाना नूरपुर द्वारा दिनांक 28 मई 2018 को गांव भदरोया, तहसील इंदौरा निवासी उत्तम चंद पुत्र मांगा राम के घर पर की गई छापेमारी के दौरान 21.05 ग्राम चिट्टा, 613 पैरावन सपास कैप्सूल और 3,000 नकद बरामद किए गए थे। इस मामले में अभियोग संख्या 151/18 धारा 21, 22, 61-85 मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नूरपुर में दिनांक 31 जुलाई 2025 को पूरी हुई। अदालत ने आरोपी उत्तम चंद को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और ?10,000 के जुमार्ने की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, आरोपी एक कुख्यात नशा तस्कर है, जिसके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। जिला पुलिस नूरपुर ने आश्वस्त किया है कि नशे के खिलाफ उसकी मुहिम जारी रहेगी और दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई की जाती रहेगी।

### राजगढ़-नेरीपुल-छैला सड़क पर दूसरे दिन भी जाम, सेब सीजन में बागवानों की बढ़ी परेशानी

दिव्य दिल्ली : सिरमौर

राजगढ़ क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क सनौरा-नेरीपुल-छैला मार्ग आज लगातार दूसरे दिन भी बाधित रहा, जिससे यात्रियों व स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जहां सोमवार को नेरीपुल के पास भारी भूस्खलन के कारण रास्ता बंद हुआ था, वहीं मंगलवार सुबह करीब 4 बजे शलेच के पास एक कैंटर बीच सड़क पर पलट गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

स्थानीय प्रशासन द्वारा जेसीबी की मदद से कैंटर को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद करीब सुबह 9 बजे मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खुल पाया। चूंकि यह मार्ग रासूमांदर, कोटखाई, ठियोग, चौपाल और रोहड़ू क्षेत्रों को सोलन से जोड़ता है और रोजाना सेब से भरे सैकड़ों ट्रक इसी मार्ग से देशभर की मंडियों की ओर रवाना होते हैं, ऐसे में सड़क के बंद होने से बागवानों को खासा नुकसान झेलना पड़ा। इसके अतिरिक्त निजी और सरकारी बसों के संचालन पर भी असर पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई। यह मार्ग न केवल चार विधानसभा क्षेत्रों की जीवनरेखा है, बल्कि हिमाचल के प्रमुख सेब उत्पादन क्षेत्रों को भी जोड़ता है। लगातार सड़क अवरुद्ध होने से प्रशासन की आपदा प्रबंधन क्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

# नूरपुर में फोरलेन निर्माण बना मुसीबत, कीचड़ और जलभराव से जनता बेहाल

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

**मानसून** के आगमन के साथ ही नूरपुर क्षेत्र के लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ गई हैं। विशेषकर पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर यात्रा करना और पैदल चलना भी अब जोखिम भरा बन गया है। नूरपुर नगर परिषद क्षेत्र में स्थित सरकारी आईटीआई, भारत सरकार के कार्यालय और गेही लगोड़ पंचायत के आसपास कीचड़ और जलभराव की स्थिति ने आमजन को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन समस्याओं का मुख्य कारण फोरलेन निर्माण कंपनी की लापरवाही है, जो निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले मलबे को व्यवस्थित तरीके से हटाने में विफल रही है। बारिश के चलते यह मलबा सड़क पर आकर जमा हो गया है, जिससे न सिर्फ दोपहिया वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों और सरकारी कर्मचारियों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बार-बार शिकायतें करने के बावजूद संबंधित विभाग और निर्माण कंपनी द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। जसूर से कंडवाल तक लगभग 10 किमी का मार्ग बुरी तरह जर्जर हो चुका है और फिसलन के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। नूरपुर के व्यापारियों ने भी इस स्थिति को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि हर बारिश के साथ फोरलेन का मलबा बहकर बाजारों में आ जाता है, जिससे दुकानों में पानी भरने लगता है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हैं। व्यापारियों ने फोरलेन निर्माण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वे "नीरो की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, जबकि शहर डूब रहा है।"स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग ने बताया कि यह समस्या सिर्फ सड़क निर्माण से नहीं, बल्कि बरसात के पानी की उचित निकासी न होने के कारण उत्पन्न हो रही है।

निर्माण कंपनी ने मलबा हटाने और जल निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता ने प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि मानसून के शेष समय में जनजीवन सामान्य रह सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

# भूस्खलन से उजड़ा नौसेना का जवान, 6 वर्षों से न्याय की आस में डटा रहा

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन नूरपुर)

**सीमाओं** की रक्षा करने वाला देश का जवान सूरम सिंह आज खुद अपने ही प्रदेश में अपने घर को बचाने के लिए लड़ रहा है। जिला कांगड़ा के नूरपुर उपमंडल की डन्नी पंचायत के खड़ेतर गांव निवासी नौसेना के जवान सूरम सिंह पिछले छह वर्षों से भूस्खलन की त्रासदी के बाद अपने पुश्तैनी घर और जमीन को बचाने के लिए लगातार प्रशासन व सरकार के आगे गुहार लगाता रहा, पर उसे अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले। 18 अगस्त 2019 को भारी बारिश से हुए भूस्खलन में उनका बड़ा हिस्सा जमीन के साथ गोशाला भी बह गई थी। जब्बर खड्ड का बहाव भी उनके घर की ओर मुड़ गया, जिससे खतरा और बढ़ गया। भारी बारिश ने उनकी बची-खुची आशा भी छीन ली। भूस्खलन की चपेट में आकर उनका मकान भी आधा टूटकर बह गया। सूरम सिंह, जो भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं और प्रधानमंत्री आवास पर विशेष ड्यूटी पर तैनात रहे हैं, ने बताया कि उन्होंने अपनी पीड़ा प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई, लेकिन राहत अब तक नहीं मिली। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और तत्कालीन वन मंत्री राकेश पठानिया से लेकर केंद्र सरकार की ज्वॉइंट सेक्रेटरी संजीव कुमार जिंदल के नेतृत्व में आई टीम तक सबने मौके का मुआयना किया, मगर हालात जस के तस बने हुए हैं। सूरम सिंह का कहना है कि यदि किराये में खर्च हुए पैसों से घर बना सकते तो अब तक बना लेते, पर सरकार की राहत योजनाओं ने केवल वादों का बोझ ही बढ़ाया। अब भारी बारिश ने उनका घर भी निगल लिया। एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने बताया कि पीड़ित परिवार को हाल ही में सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है और मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही हर संभव सहायता की जाएगी।

### 20 लाख रुपये की लागत से गाँव लाहरी गुजरां में बनाया जाएगा नेचर पार्क

दिव्य दिल्ली : करूनीत रंधावा (पठानकोट)

पंजाब सरकार वन विभाग द्वारा 20 लाख रुपये की लागत से गाँव लाहरी गुजरां में एक नेचर पार्क का निर्माण कराएगी। यह घोषणा पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने पंजाब शिक्षा क्रांति अभियान के तहत 7 लाख रुपये की लागत से पुनर्निर्मित राजकीय प्राथमिक स्मार्ट स्कूल लाहरी गुजरां का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए की। संबोधित करते हुए, कैबिनेट मंत्री कटारूचक ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गांव लाहड़ी गुजरां में बनने वाले नेचर पार्क में रनिंग ट्रैक, महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग-अलग ओपन जिम, बैठने के लिए बेंच और सुंदर पौधे होंगे।

## इंदौरा से भेजी गई दूसरी राहत सामग्री की खेप, जीवन-यापन के सामान शामिल

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

**नूरपुर** प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से आज दूसरी बार राहत सामग्री की खेप रवाना की गई। इस बार जीवन-यापन से जुड़ी आवश्यक सामग्री को वाहन में भरकर भेजा गया, जिसका नेतृत्व स्थानीय विधायक मलेंद्र राजन ने किया' विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहयोग की अपील की थी, जिस पर इंदौरावासियों ने तत्परता से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी एक छोटी सी अपील पर क्षेत्रवासियों ने दिल खोलकर सहयोग किया और बड़ी मात्रा में सामग्री एकत्रित की गई' उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए लगातार कार्य कर रही है और इंदौरा क्षेत्र भी हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।इस अवसर पर एसडीएम डॉ सुरिंद्र ठाकुर, बीडीओ सुदर्शन सिंह,पूर्व जिला अध्यक्ष कर्ण सिंह पठानिया, इंदौरा प्रधान भूपाल कटोच, पूर्व उपप्रधान मनोहर सिंह, कांग्रेस कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा, अनिल कटोच, उमा कांत सूदन, धर्मेंद्र निक्का सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

## रावी किनारे सर्च ऑपरेशन: पंजाब पुलिस और आईटीबीपी ने चलाया संयुक्त अभियान

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

जम्मू कश्मीर में चल रही श्री अमरनाथ जी की यात्रा व संदिग्धों पर चौकसी का प्रयोग करने के मकसद को लेकर पंजाब पुलिस व आईटीवीपी फोर्स की ओर से रावी नदी के किनारे लगते गांव राजपुरा, कमुयाल, सिद्दोडी, हरूर , निजि कपंनी के साथ लगते क्षेत्र में , पंजाब पुलिस के डीएसपी सुखवीर सिंह के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में लगभग लगभग चालीस अधिकारियों व जवानों की ओर से सर्च ओपरेशन को किया गया। इस सर्च ओपरेशन में डीएसपी सुखवीर सिंह, एएसआई धर्म पाल , एएसआई मुखतियार सिंह व आईटीवीपी के जवानों सहित इस सर्च ओपरेशन में भाग लिया। सर्च ओपरेशन को लीड करने वाले डीएसपी सुखवीर सिंह ने बताया कि इस समय पावन श्री अमरनाथ जी की यात्रा व सुरक्षा व्यवस्था को बढावा देने के लिए ,उनकी पुलिस व आईटीवीपी फोर्स की ओर से पूरे क्षेत्र में चौकसी का प्रयोग किया जा रहा है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस क्षेत्र में घुसपैठ न कर सके। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों , पुलिस जवानों व आईटीवीपी फोर्स ने रावी नदी के साथ सटे गांवों में रह रहे गुज्जरों के डेरों में भी गहन सर्च ओपरेशन को चलाया तथा गुज्जरों के मुखियों को हिदायत दी की , यदि कोई भी नया व संदिग्ध व्यक्ति उनके डेरों पर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते , पुलिस कार्रवाई कर सके।

## जिला प्रशासन लाहौल एवं आयुष विभाग द्वारा योग शिविर का आयोजन

दिव्य दिल्ली : रंजीत (लाहौल)

आगामी ट्राइबल फेयर 2025 (दिनांक 14 से 16 अगस्त 2025) के प्रचार-प्रसार एवं स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु आज दिनांक 2 अगस्त 2025 को जिला प्रशासन लाहौल एवं आयुष विभाग केलांग द्वारा एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लाहौल-स्पीति के आमजन के साथ-साथ सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं महिला मंडल (लोअर एवं अपर केलांग) की सहभागिता रही। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त लाहौल-स्पीति की गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर एसडीएम केलांग आकांक्षा शर्मा, सहायक आयुक्त कल्याणी गुप्ता, डीएसपी केलांग रश्मि शर्मा, डीएफओ अंकित, जिला आयुष अधिकारी डॉ. वनीता शर्मा एवं डॉ. सुरेश भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। डॉ. वनीता शर्मा एवं डॉ. सुरेश ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए योग के महत्व तथा इसके स्वास्थ्य लाभों के विषय में जानकारी साझा की। तत्पश्चात उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा सामूहिक रूप से विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना एवं आगामी ट्राइबल फेयर 2025 के प्रति जन-भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस प्रकार के आयोजन जनसामान्य को न केवल बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि पारंपरिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जोड़ते हैं।

## प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने राजीव बिंदल पर किया पलटवार

### लॉटरी तो राजीव बिंदल की निकली है क्योंकि भाजपा की आपसी तकरार के चलते राजीव बिंदल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला

दिव्य दिल्ली : हमीरपुर

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रेम कौशल ने कहा कि राजीव बिंदल ने जो हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू करने पर बयान दिया है। लॉटरी तो राजीव बिंदल की निकली है क्योंकि भाजपा की आपसी तकरार के चलते राजीव बिंदल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई तानाशाह रवैया नहीं अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ही तानाशा रवैया अपना रही है। जिसको राजीव बिंदल हिमाचल में कट पेस्ट के तौर पर पेश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हिमाचल की प्रदेश सरकार हिमाचल की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस तरह के निर्णय लिए ले रही है।वही प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सीजफायर किया है। प्रेम कौशल ने कहा कि मोदी सरकार ने ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर का फैसला लिया है। प्रेम कौशल ने कहा कि ट्रंप केंद्र के नेतृत्व को लगातार जलील कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री की विदेश नीति के कारण हुआ है जो की पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश का जो आकलन किया गया है उसे पर प्रेम कौशल ने सहमति जताई है उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों के विकास का मॉडल दूसरे राज्यों के विकास से अलग होना चाहिए। प्रेम कौशल ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में जो विकास किया जा रहा है। उसके विकास का तरीका बदलना होगा क्योंकि पहाड़ों की अपनी भौगोलिक स्थिति है जबकि मैदानी क्षेत्र की अपनी भौगोलिक स्थिति है हर स्थिति के अनुसार कार्य होना चाहिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश में विकास के मॉडल में बदलाव करने की आवश्यकता है।वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के राजस्व में बढ़ोतरी होने पर खुशी जाहिर की है उन्होंने कहा कि बरसों से हिमाचल प्रदेश का विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहा था। लेकिन प्रदेश के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के विद्युत बोर्ड ने 315 करोड रुपए का इजाफा किया है वह हिमाचल के लिए बहुत ही सराहनीय बात है। प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सूक्खु सरकार हिमाचल की आर्थिक को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन प्रयास कर रही है।

### रणजीत सागर बांध परियोजना की झील में दो मीटर से अधिक जलस्तर बढा

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

पूरे क्षेत्र में भारी वर्षा होने व चमेरा प्रोजेक्ट से एक गेट को साढे पांच मीटर खोलने पर 92695 क्यूसिक पानी का भारी वहाव रणजीत सागर बांध परियोजना की झील में आ रहा है, जिससे दूसरे दिन भी बांध परियोजना की झील में दो मीटर से अधिक जलस्तर बढा है। गत दिवस आरएसडी की झील में जलस्तर 510.20 मीटर तक था जो एक ही दिन में भारी वर्षा होने व चमेरा प्रोजेक्ट से अधिक मात्रा में पानी का बहाव आने पर 512.30 मीटर तक जलस्तर बढा है। बांध प्रशासन अनुसार, बांध परियोजना की झील में 527.91 मीटर तक पानी पीछे रखने की क्षमता है , जिससे अभी लगभग लगभग 15 मीटर और अधिक पानी समाने की क्षमता है।

## मलोट में पानी की भारी किल्लत, महिलाओं ने जताया रोष

दिव्य दिल्ली : इंदौर

**इंदौरा** मंडल के मलोट क्षेत्र में पिछले लंबे समय से चल रही पेयजल संकट की समस्या ने स्थानीय निवासियों को बेहद परेशान कर दिया है। पानी की लगातार कमी को लेकर लोगों में आक्रोश है। इसी मुद्दे पर स्थानीय महिला मंडल प्रधान पुष्पा देवी व अन्य महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से पानी की आपूर्ति ठप है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए न केवल पंचायत स्तर पर, बल्कि जलशक्ति विभाग के अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी दो दिनों में समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो उन्हें मजबूरन खाली बर्तन लेकर विभागीय कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन करना पड़ेगा। इस संबंध में जब सहायक अभियंता अनिल ठाकुर से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि विभाग को मामले की जानकारी है और फिलहाल समस्या की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397